epaper.dehatsandesh.com

3 राणा ने जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण का दिया आश्वासन

5 महज 21 साल की उम्र में शैफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास

8 काबुली चने की खेती कैसे करें

मौसम जम्मू — न्यूनतम 8 — अधिकतम 18

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-316 | जम्मू तवी, वीरवार 25 दिसम्बर, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

अटल जी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकते रहेंगे : राजनाथ

लखनऊ, 24 दिसम्बर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लखनऊ में 'अटल गीत गंगा कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए कहा कि एक जनप्रिय राजनेता के रूप में अटल जी ने देशवासियों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। अटल जी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकते रहे और हमेशा चमकते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ सिंह ने 'अटल महानायक' पुस्तिका का विमोचन एवं प्रथम ई-बुक का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर अटल बिहारी बाजपेई साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने लिखा है चीर निशा का वक्ष, पुनः चमकेगा दिनकर।

। अटल जी ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों से आत्मीय संबंध बनाया और अपने स्नेहिल, सहज व्यक्तित्व से लोगों के दिल में खास जगह बनायी। अटल जी ने सार्वजनिक जीवन की उथल-पुथल और शोर में भी कविता के कोमल स्वर को सदा जीवित रखा। एक जनप्रिय राजनेता के रूप में अटल जी ने देशवासियों के मन पर अमिट छाप छोड़ी

रक्षामंत्री ने कहा कि अटल जी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वे अपने विरोधियों पर भी हमला करते थे तब भी शब्दों की शालीनता को बिना ताख पर रखे बड़ी से बड़ी बात कह जाते थे। अटल जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने लाहौर में एक भाषण दिया था। वहाँ अटल जी के भाषण से श्रोता इतने प्रभावित हुए थे कि नवाज़ शरीफ़ ने मजाक में कहा था वाजपेयी साहब आप तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं

। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा भारत रत्न श्रद्धेय पं0 अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ कुमार विश्वास ने एकल काव्य पाठ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री आशीष पटेल, मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सांसद डा. दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद बृजलाल, राज्यसभा सांसद संजय सेठ एवं लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहे।

पुलिस के सामने नशा व मानव तस्करी, साइबर अपराध बड़ी चुनौती : अमित शाह

चंडीगढ़, 24 दिसंबर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा समेत देश की पुलिस के सामने इस समय नशा और मानव तस्करी, साइबर अपराध व संगठित अपराध बड़ी चुनौती है। इससे निपटने में हरियाणा पुलिस पूरी तरह सक्षम है। हरियाणा के कई जिले देश की राजधानी से सटे हुए हैं और एनसीआर का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यहां की अपराधिक गतिविधियां देश के अन्य राज्यों से भिन्न हैं। हरियाणा पुलिस केसों को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है।

अमित शाह बुधवार को पंचकूला में हरियाणा पुलिस के रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच-93 की भव्य पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परेड के बाद 5061 नव-प्रशिक्षित जवान हरियाणा पुलिस का हिस्सा बने।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज की परेड कमांड महिला सिपाही

> "पिछले दस वर्षों के भीतर देश की सभी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आज पूरे देश में अमन चैन व शांति का माहौल है

निशु ने किया। भारत में नए कानून लागू होने के बाद यह पहला बैच है जिसे नए कानूनों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले पुलिस के जवान अंग्रेजों के समय से लागू कानूनों के आधार पर पढ़ाई करके पुलिस बल का हिस्सा बनते थे। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें 93 प्रतिशत महिलाएं हैं तो 85 प्रतिशत युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट हैं। पुलिस का हिस्सा बने युवाओं की औसत आयु 26 साल है। अमित शाह ने कहा कि आज हरियाणा का विस्तार हो रहा है। 01 नवंबर 1966 को हरियाणा में छह जिले व एक रेंज थी। आज 23 जिले बन चुके हैं।

गृहमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक देश में वामपंथी आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर का उग्रवाद, नार्थ ईस्ट की गतिविधियों के कारण देश में असुरक्षा का माहौल था। पिछले दस वर्षों के भीतर देश की सभी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आज पूरे देश में अमन चैन व शांति का माहौल है। गृहमंत्री ने कहा कि क्नए कानूनों में फोरेंसिक साइंस की भूमिका को अहम बनाया गया है। 07 साल से अधिक की सजा वाले गुनाह में फोरेंसिक विजिट जरूरी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ऑपरेशनों की सराहना करते हुए कहा कि 05 हजार युवाओं के पुलिस का हिस्सा बनने से प्रदेश के पुलिस थानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और काम का बोझ कम होगा।

इसके बाद परेड कमांडर निशु ने मुख्य अतिथि से परेड की स्वीकृति ली। पुलिस दस्ते की पहली 12 टुकडियों का नेतृत्व महिला सिपाहियों द्वारा किया गया।

खबर संक्षेप

जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में 'हिमस्खलन' की चेतावनी जारी

श्रीनगर, 24 दिसंबर। अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को देखते हुए बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में 'हिमस्खलन' की चेतावनी जारी की है।डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों के लिए कम खतरे वाले 'हिमस्खलन' की चेतावनी जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों से 2,800 मीटर ऊपर 'हिमस्खलन' होने की संभावना है। लोगों से 'हिमस्खलन' की आशंका वाले इलाकों से बचने और सरकारी सलाह मानने को कहा गया है। इस हफ़्ते जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी हुई है।

सीआरपीएफ शिविर में नाश्ते के समय घुसा तेंदुआ, हमले में जवान घायल

श्रीनगर, 24 दिसंबर। बुधवार सुबह अनंतनाग के कपरान इलाके में सीआरपीएफ शिविर में उस समय दहशत फैल गई जब नाश्ते के समय एक तेंदुआ शिविर में घुस आया और कर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे एक जवान घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह के समय कपरान शिविर में हुई, जब जवान नाश्ते के लिए मेस में इकट्ठा थे। अचानक एक तेंदुआ शिविर में घुस आया और कर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना में एचसी कमलेश कुमार नाम का एक जवान घायल हो गया। उसे तुरंत पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, जहां उसका तुरंत इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि घायल जवान की हालत स्थिर है।

जम्मू में बाहरी वाहनों के पुनः पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय

जम्मू तवी, 24 दिसंबर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जम्मू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीकरण नंबर वाले उन मोटर वाहनों के मालिकों को तत्काल पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से जम्मू संभाग में संचालित किए जा रहे हैं।

सूचना में कहा गया है कि ऐसे वाहनों को बिना पुनः पंजीकरण के 12 महीने से अधिक समय तक जम्मू में रखना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 का उल्लंघन है। इससे वाहन नियमन, वाहनों की पहचान (ट्रेसबिलिटी) और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित जोखिम उत्पन्न होते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए, वाहन मालिकों को सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी से नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुनः पंजीकरण न कराने की स्थिति में संबंधित वाहनों को जब्त किया जा सकता है तथा उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत जुर्माना, निरुद्धीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एलजी लद्दाख ने क्रिसमस की शुभकामनाएँ दीं

लेह, 24 दिसंबर। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के राज्यपाल श्री कवींदर गुप्ता ने लद्दाख के लोगों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय को, क्रिसमस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। अपने संदेश में, राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस, जो यीशु मसीह के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है, प्रेम, करुणा, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएँ मानवता को निःस्वार्थ सेवा, सौहार्द और आपसी सम्मान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कवींदर गुप्ता ने यह भी बताया कि लद्दाख अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सौहार्द की परंपरा के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार एकता के बंधनों को और मजबूत करेगा और केंद्रीय शासित प्रदेश में सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रहित में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव', यह भाजपा का नहीं बल्कि देश का अभियानः शिवराज

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार होने वाले चुनाव विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा हैं। देश में 5 साल, 12 महीने और 365 दिन चुनाव की तैयारी चलती रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

शिवराज सिंह ने बुधवार को यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एक चुनाव की आचार संहिता लागू होती है, फिर दूसरे चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, जिसके कारण नई योजनाएं शुरू नहीं हो पातीं और विकास कार्य ठप हो जाते हैं। उन्होंने इसे समय और संसाधनों की बड़ी बर्बादी बताया।

उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' राष्ट्रहित में है और यह अभियान गैर राजनीतिक है। यह भाजपा का अभियान नहीं बल्कि देशहित का अभियान है। इस पहल को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 'वूमेन फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन', 'सीए फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन', 'डॉक्टर फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन' और 'प्रोफेसर फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे अलग-अलग मंच बनाने की अपील की।

लोकसभा सदस्यों को मिली मनपसंद भाषा में बोलने की सुविधा, प्रधानमंत्री ने पहल को सराहा

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। भारत की विविध संस्कृति और भाषाओं का सम्मान करने के लिए 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र बहुत खास रहा। इस बार सांसदों ने संविधान की अनुसूची आठ में बताई गई 22 भाषाओं में समानांतर अनुवाद सेवा का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि सांसद अपनी भाषा में बोल सकते हैं और बाकी लोग उसे अपनी भाषा में सुन सकते हैं। यह सेवा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त को शुरू की थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की बहुभाषी विरासत को मनाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष को इस काम के लिए बधाई दी। अब सांसद अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकते हैं। इससे सांसदों के विचार लोगों तक आसानी से पहुंचेंगे और संसद में हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार अध्यक्ष बिरला ने बार-बार कहा कि यह पहल संविधान की भावना के अनुसार है, क्योंकि संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को मानता है। हर भाषा का अपना इतिहास, संस्कृति और पहचान है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने पदोन्नत किए गए 16 आईएएस अधिकारियों में एसडीएम उड़ी भी शामिल हैं

जम्मू, 24 दिसंबर। गृह मंत्रालय ने सोलह आईएएस अधिकारियों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया है जिसमें शुभंकर प्रत्यूष पाठक भी शामिल हैं जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट उरी के रूप में तैनात हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पदोन्नत अन्य अधिकारियों में सम्यक एस जैन, इशिता राठी, आयुषी, मंजूनाथ आर, वैरोकपम पुंशिबा सिंह, कमलेश्वर राव, तुषार आनंद, श्रीनिवास सादी, यशवंत मीना, सोविग्या एस चंद्रा, मोहम्मद शब्बीर, शिवम चंद्रा, मुकुल बेनीवाल, कनिका और राघवेंद्र मीना शामिल हैं।

कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान बढ़कर हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज

श्रीनगर, 24 दिसंबर । कश्मीर में ठंड से राहत मिली है क्योंकि अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान बढ़कर हिमांक बिंदु से ऊपर हो गया है। हाल ही में हुई बर्फबारी और बारिश के बाद आसमान में बादल छाए रहने के कारण कश्मीर में ठंड से राहत मिली और अधिकांश स्थानों पर रात का तापमान बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल और उत्तर में स्थित प्रसिद्ध स्कीइंग रिसॉर्ट गुलमर्ग को छोड़कर न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहा। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछली रात के 2.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक और मौसम के सामान्य तापमान से 5.4 डिग्री अधिक था। घाटी के अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया जो 1.8 से 5.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटन स्थलों में तापमान शून्य से नीचे चला गया, जहां पारा क्रमशः -4.2 डिग्री सेल्सियस और -2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दक्षिण कश्मीर के काज़ीगुंड में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस और कोकरनाग में 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाडा में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

एक कुख्यात ड्रग तस्कर की तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 24 दिसंबर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बुधवार को एक कुख्यात ड्रग तस्कर की तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस का आरोप है कि ये संपत्तियां अवैध ड्रग तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थीं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने वाले ढांचे को ध्वस्त करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत श्रीनगर पुलिस ने दो मंजिला आवासीय मकान और दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ एक कनाल से अधिक जमीन जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां कुख्यात ड्रग तस्कर एजाज अहमद मीर की हैं जो शहर के पालपोरा नूरबाग इलाके का निवासी है। पुलिस ने आगे बताया कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में संलिप्त है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि आरोपी ने ड्रग तस्करी से प्राप्त अवैध धन से ये संपत्तियां अर्जित की थीं।

यूटी लद्दाख के निवर्तमान मुख्य सचिव के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित

एलजी कविंदर गुप्ता ने डॉ. कोटवाल की अनुकरणीय सेवा और प्रशासनिक दक्षता की सराहना की

कारगिल। माननीय उपराज्यपाल लद्दाख, श्री कविंदर गुप्ता ने कारगिल में आयोजित एक विदाई समारोह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवर्तमान मुख्य सचिव डॉ. पवन कोटवाल, आईएएस को उनके सेवानिवृत्त होने के अवसर पर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) कारगिल, जिला प्रशासन कारगिल तथा जिला पुलिस कारगिल द्वारा किया गया।

विदाई रात्रिभोज डॉ. पवन कोटवाल, आईएएस को समर्पित एक विशेष श्रद्धांजलि था। लद्दाख प्रशासन के साथ उनका कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने प्रधान सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और योजना, विकास एवं निगरानी; स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा; वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण; तथा राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियाँ निभाईं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सक्रिय, सुधारोन्मुख रणनीतियों के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अनेक ऐतिहासिक पहलें सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुईं। आगे बढ़ते हुए, 9 जून 2023 को उन्होंने माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार का महत्वपूर्ण दायित्व संभाला।

क्रिसमस एक त्यौहार शांति दूत के नाम

क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे शायद दुनिया के सर्वाधिक लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. आज यह त्यौहार विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी समान जोश के साथ मनाया जाता है. भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के साथ क्रिसमस का त्यौहार भी पूरी तरह घुल-मिल गया है. सदियों से यह त्यौहार लोगों को खुशियां बांटता और प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता रहा है. यह त्यौहार हमारे सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब भी है, जो विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारे को मजबूती देता आया है. क्रिसमस का अर्थ मानव मुक्ति और समानता है. बाइबिल के अनुसार, ईश्वर ने अपने भक्त याशायाह के माध्यम से 800 ईसा पूर्व ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में एक राजकुमार जन्म लेगा और उसका नाम इमेनुएल रखा जाएगा. इमेनुएल का अर्थ है 'ईश्वर हमारे साथ'. याशायाह की भविष्यवाणी सच साबित हुई और यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार हुआ.

स्वर्गदूतों ने दिया था यीशु जन्म का संदेश

ऐसी मान्यता है कि यीशु के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने सर्वोच्च गगन में परमेश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपापात्रों को शांति यह संदेश कुछ चरवाहों को दिया था। गत हजारों वर्ष से ख्रीस्त जयंती की मंगलमय बेला में करोड़ों कंठों से इस संदेश की प्रतिध्वनि गूंजती आ रही है। इस संदेश की सुंदरता इसमें है कि यीशु के जन्म के साथ उदित होने वाली नई विश्वव्यवस्था की झलक इसमें निहित है। पृथ्वी पर मानवों के शांतिपूर्ण जीवन में ईश्वर की स्वर्गीय महिमा प्रतिबिंबित है। मनुष्य में ईश्वर महिमान्वित होता है। यीशु ईश्वर और मनुष्य के बीच की सजीव कड़ी है। सच्ची शांति अच्छे मन का अनुभव है। ऐसी शांति तभी संभव है जबकि हृदय भय और मृत्यु से, दर्द और पीड़ा से मुक्त हो। लेकिन हम एक भ्रष्ट और दमनकारी संसार में जीते हैं जहां भय राज करता है और शांति की जड़ कमजोर है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि यहां सच्चे दिलवालों की संख्या निराशाजनक रूप से कम है। जहां धन और बल मनुष्य के भविष्य में नियंता हों, जहां ईमानदारी और नैतिकता को कमजोरी के लक्षण माना जाता हो, वहां शांति और सच्चाई का बना रहना असंभव है। आज संसार में जो शांति दिखाई पड़ती है, वह हृदय की सच्चाई से नहीं बल्कि हथियारों के समझौते से निकली है। शायद यीशु की विश्वव्यवस्था की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर मानव किसी भी जाति-वर्ग-वर्ण भेद के बिना ईश्वर की संतान बन सकता है। ईश्वर का जो रूप यीशु ने लोगों को बताया वह वास्तव में मन को छूने वाला है। ईश्वर इतना उदार है कि वह भले और बुरे, दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। ईश्वर सबको प्यार करता है, सबका ख्याल रखता है और पश्चातापी पापी को क्षमा करता है। मनुष्य को विधाता पर भरोसा रखना चाहिए। इस परम पिता की योग्य संतान बनने के लिए मनुष्य को दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना तथा उनकी गलतियों को क्षमा करना है। इस नई व्यवस्था की मूल आज्ञा बिना शर्त प्रेम है और इसका स्वर्णिम नियम है- दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो।

बालक यीशु के जन्म की सबसे पहली खबर इस दुनिया के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को मिली थी. वे कड़ी मेहनत करने वाले गड़रिये थे. सर्दी की रात जब उन्हें यह खबर मिली तो वे खुले आसमान के नीचे खतरों से बेखबर सोती हुई अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे. एक तारा चमका और स्वर्ग-दूतों के दल ने गड़रियों को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है, जो तुम्हारा राजा होगा. पूरी दुनिया के गरीब यह खबर सुनकर जहां खुश हुए, वहीं गरीबों पर जुल्म करने वाला राजा हेरोदेस नाराज हो गया. उसने अपने राज्य में 2 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को कत्ल करने का आदेश जारी कर दिया, ताकि उसकी सत्ता को भविष्य में किसी ऐसे राजा से खतरा न रहे. अच्छाई को देखकर बुराई करने वाले इसी तरह दुखी और नाराज होते हैं. यही शैतानियत का प्रतीक है. ईसा मसीह इसी शैतानियत को तो खत्म करने के लिए आए थे.

ईसा मसीह ने मानव के रूप में जन्म लेने के लिए किसी संपन्न व्यक्ति का घर नहीं चुना. उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के घर की गोशाला में घास पर जन्म लिया. दरअसल, वे गरीब, भोले-भाले और शोषित व पीड़ित लोगों का उद्धार करने आये थे. इसीलिए उन्होंने जन्म से ही ऐसे लोगों के बीच अपना स्थान चुना. यह बहुत बड़ा संदेश था.

30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह ने सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने जनता को दीन-दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेमभाव से रहने, लालच न करने, ईश्वर और राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने, आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह न करने का उपदेश दिया. आज ईसा मसीह के दिए हुए संदेशों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भले ही सामाजिक बुराइयों ने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन वे आज भी समाज में विद्यमान हैं और गरीबों, लाचारों, शोषितों, पीड़ितों और दलितों को उनका शिकार होना पड़ता है.

ईसा मसीह ने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया था. उन्होंने बार-बार कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और भले ही इस दुनिया में क्रूरता, अन्याय और गैर-बराबरी जैसी अनेक बुराइयां हैं, पर ईश्वर के घर में सभी बराबर हैं. उन्होंने ऐसा ही समाज बनाने पर जोर दिया, जिसमें क्रूरता व अन्याय की जगह न हो और सभी प्रेम और समानता के साथ रहें. ऐसी ही एक कहानी बाइबिल में आती है, जो एक सामरी संप्रदाय की स्त्री की है. जब ईसा मसीह ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? दरअसल, यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे और उन्हें कमतर मानते थे. लेकिन ईसा ने उसके हाथ का पानी पिया. ईसा मसीह ने दलित, दमित और असहाय लोगों को आशा और जीवन का संदेश दिया. उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाया. यही वजह थी कि उन्हें क्रॉस पर मृत्युदंड भी दिया गया. लेकिन दूसरों के हित में काम करने वाले मृत्युदंड से कब भयभीत हुए हैं. क्रिसमस का त्यौहार कई चीजों के लिए खास होता है जैसे क्रिसमस ट्री, स्टार, गिफ्टस आदि. और हां, कई लोग मानते हैं क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देता है. सांता क्लॉज को याद करने का चलन 4वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था और वे संत निकोलस थे जो तुर्किस्तान के मीरा नामक शहर के बिशप थे. सांता क्लाज़ लाल व सफेद ड्रेस पहने हुए, एक वृद्ध मोटा पौराणिक चरित्र है, जो रेन्डियर पर सवार होता है तथा समारोहों में, विशेष कर बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. क्रिसमस उम्मीदों और खुशियों का त्यौहार है. ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी अमीरी-गरीबी, जातिवाद और सामाजिक विसंगतियां समाज में मौजूद हैं. जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे और गरीब व लाचार लोगों के दुख-दर्द को समझेंगे और ईसा मसीह की तरह अपनी कोशिशों से उनके चेहरे पर थोड़ी-सी मुस्कान लाएंगे, तभी हमें क्रिसमस की वास्तविक खुशियां मिलेंगी.

कैसे हुई सांता क्लॉज की प्रसिद्धि...

सांता क्लॉज को भले ही आधुनिक बाजारवाद का प्रतीक माना जाए लेकिन इस किंवदंती की उत्पत्ति सदियों पुरानी है। माना जाता है कि तीसरी सदी में तुर्की में जन्मे संत निकोलस का ही आधुनिक रूप है सांता क्लॉज। अपने धर्मालु और दयालु स्वभाव के कारण वे जबर्दस्त लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी तमाम पुश्तैनी धन-दौलत दान कर दी थी और दूर-दूर तक सफर करके वे गरीबों की मदद किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि के साथ-साथ उनसे जुड़ी किंवदंतियां भी फैलती गईं। बच्चों के प्रति उनके स्नेह की कथाएं विशेष रूप से प्रचलित हुईं। 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि बड़े पैमाने पर मनाई जाने लगी। माना जाता है कि सेंट (संत) निकोलस का नाम ही बिगड़कर पहले सिंतर क्लॉस और फिर सांता क्लॉज हो गया। योरप में खूब फैलने के बाद सांता क्लॉज की प्रसिद्धि 18वीं सदी में अमेरिका पहुंची। 1773-74 में न्यूयॉर्क में बसे हॉलैंड मूल के परिवारों ने सामूहिक रूप से सिंतर क्लॉस की पुण्यतिथि मनाई। फिर 1804 में न्यूयॉर्क हिस्टॉरिकल सोसायटी की वार्षिक सभा में उसके एक सदस्य जॉन पिंटर्ड ने संत निकोलस के लकड़ी के कटआउट बंटवाए। इनमें संत की छवि काफी कुछ वैसी ही थी जैसी आज सांता की छवि हमारे सामने है। तब तक संत निकोलस/ सिंतर क्लॉस/ सांता क्लॉज का क्रिसमस के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। फिर 1822 में क्लेमेंट क्लार्क मूर ने अपनी तीन बेटियों के लिए एक लंबी कविता लिखी एन अकाउंट ऑफ ए विजिट फॉम सेंट निकोलस। इसमें सेंट निकोलस को एक गोलमटोल, हंसमुख बुजुर्ग बताया गया, जो क्रिसमस की पूर्व रात्रि में रेनडियर वाली गाड़ी में उड़ते हुए आते हैं और चिमनी केरास्ते घरों में प्रवेश कर घर में टंगी जुराबों में बच्चों के लिए उपहार छोड़ जाते हैं। यह कविता जब प्रकाशित हुई तो अमेरिका भर में सेंट निकोलस/ सांता क्लॉज लोकप्रिय हो गए। जर्मन मूल के अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट 1863 से प्रति वर्ष सांता की नई छवि गढ़ने लगे। 1880 के दशक तक सांता की छवि वह रूप ले चुकी थी, जिससे आज हम सब परिचित हैं।

क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा

क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा जर्मनी में दसवीं शताब्दी के बीच शुरू हुई और इसकी शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति बोनिफेंस टुयो नामक एक अंगरेज धर्मप्रचारक था। इसके बाद अमेरिका के एक आठ साल के बीमार बच्चे ने क्रिसमस पेड़ को अपने पिता से सजवाया तब से क्रिसमस ट्री को रंग-बिरंगी बत्तियों, फूलों और कांच के टुकड़ों से सजाया जाने लगा। इंग्लैंड में 1841 में राजकुमार पिंटो एलबर्ट ने विंजर कासल में क्रिसमस ट्री को सजावाया था। उसने पेड़ के ऊपर एक देवता की दोनों भुजाएं फैलाए हुए मूर्ति भी लगवाई, जिसे काफी सराहा गया। क्रिसमस ट्री पर प्रतिमा लगाने की शुरुआत तभी से हुई। पिंटो एलबर्ट के बाद क्रिसमस ट्री को घर-घर पहुंचाने में मार्टिन लूथर का भी काफी हाथ रहा। क्रिसमस के दिन लूथर ने अपने घर वापस आते हुए आसमान को गौर से देखा तो पाया कि वृक्षों के ऊपर टिमटिमाते हुए तारे बड़े मनमोहक लग रहे हैं। मार्टिन लूथर को तारों का वह दृश्य ऐसा भाया कि उस दृश्य को साकार करने के लिए वह पेड़ की डाल तोड़ कर घर ले आया। घर ले जाकर उसने उस डाल को रंगबिरंगी पत्रियों, कांच एवं अन्य धातु के टुकड़ों, मोमबत्तियों आदि से खूब सजा कर घर के सदस्यों से तारों और वृक्षों के लुभावने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। वह सजा हुआ वृक्ष घर सदस्यों को इतना पसंद आया कि घर में हर क्रिसमस पर वृक्ष सजाने की परंपरा चल पड़ी। 1920 की बात है, सान फ्रांसिस्को शहर में पांच साल की बालिका की हालत गंभीर थी। उसके पिता सैंडी ने कुछ बड़े-बड़े मिट्टी के हंडों पर चित्रकारी की और उन्हें घर से सड़क की दूसरी तरफ रस्सी पर लटका कर दिखाया। वे इतने सुंदर लगे कि काफी लोग उन्हें देखने को इकट्ठे हो गए। सौभाग्य की बात थी कि नए साल तक बालिका भी ठीक हो गई। इस घटना से सैंडी बड़ा चकित हुआ। अब वह लोगों को क्रिसमस वृक्ष सजाने के अलावा लगाने के लिए भी कहता। उसने कैलिफोर्निया में एक संस्था बनाई, जो पेड़ लगाने के उत्सुक लोगों को रेडवुड वृक्ष के पौधे मुफ्त भेजती थी। सैंडी ने 20 साल तक रेडियो, समाचार-पत्रों आदि में लेख और व्याख्यान देकर लोगों को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित किया।

क्रिसमस ट्री की कथा है कि जब महापुरुष ईसा का जन्म हुआ तो उनके माता-पिता को बधाई देने आए देवताओं ने एक सदाबहार फर को सितारों से सजाया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर साल सदाबहार फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री प्रतीक के रूप में सजाया जाता है।

विदेशों में कैसे सजाया जाता है क्रिसमस ट्री

- योरपीय मुल्कों में क्रिसमस की पूर्व संध्या को क्रिसमस ट्री दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस पर बिजली के रंगबिरंगे बल्ब जगमगाते रहते हैं। देश-विदेश के महकते फूल भी इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। हीरे-मोती से जड़े कंगन इसकी पतली-पतली टहनियों में बड़ी तरकीब से पिरोए जाते हैं। ये कंगन अपनी बहुरंगी आभा से क्रिसमस ट्री को और भी ज्यादा रोशन करने लगते हैं।
- अमेरिका के अरबपति तो क्रिसमस ट्री की विशेष सज्जा के लिए कुछ खास किस्म के कीमती आभूषणों का प्रयोग करते हैं। ये आभूषण हवा के साथ-साथ तरह-तरह की खुशबू से महकने भी लगते हैं। बाद में इन आभूषणों को गरीबों में बांट दिया जाता है।
- स्विस वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रिसमस के पेड़ में आनुवांशिक परिवर्तन कर उन्हें स्वयं ही प्रदीप्त होने वाला बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आनुवांशिक परिवर्तन वाले पेड़ विद्युत सर्पमीन की तरह आवाज भी निकाल सकेंगे।
- इस संदर्भ में ज्यूरिख के वैज्ञानिक डॉ. बर्नार्ड का कहना है क्रिसमस ट्री में जैविक परिवर्तन कर प्रकाश संश्लेषण के जरिए विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। हां, आनुवांशिक परिवर्तन के उपरांत इन पेड़ों को कहीं भी लगाया जा सकता है।
- इंग्लैंड के निवासी जन्मदिन, विवाह एवं मृत्यु पर क्रिसमस ट्री जमीन में रोपते हैं, ताकि धरती सदा हरियाली से झूमती रहे।

गो कैरोलिंग दिवस

दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस से ठीक पहले उनके संदेशों को भजनों (कैरल) के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाने की प्रथा को विश्व के विभिन्न हिस्सों में 'गो कैरोलिंग दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

दिल्ली स्थित रोमन कैथलिक चर्च के प्रवक्ता फादर डोमेनिक इमैनुअल के अनुसार क्रिसमस से ठीक पहले कैरोलिंग दिवस के दिन ईसाई धर्मावलंबी रंगबिरंगे कपड़े पहनकर एक-दूसरे के घर जाते हैं और भजनों के माध्यम से प्रभु के संदेश का प्रचार-प्रसार करते हैं। उन्होंने कहा, 'प्रभु की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के समूह में भजन गायन का यह सिलसिला क्रिसमस के बाद भी कई दिनों तक जारी रहता है। कैरल एक तरह का भजन होता है जिसके बोल क्रिसमस या शीत ऋतु पर आधारित होते हैं। ये कैरल क्रिसमस से पहले गाए जाते हैं।'' डोमेनिक ने कहा, 'ईसाई मान्यता के अनुसार कैरल गाने की शुरुआत यीशु मसीह के जन्म के समय से हुई। प्रभु का जन्म जैसे ही एक गौशाला में हुआ वैसे ही स्वर्ग से आए दूतों ने उनके सम्मान में कैरल गाना शुरू कर दिया और तभी से ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस के पहले ही कैरल गाना शुरू कर देते हैं।'' फादर डोमेनिक ने कहा कि गो कैरोलिंग दिवस एक ऐसा मौका होता है जब लोग बड़े धूमधाम से प्रभु यीशु की महिमा, उनके जन्म की परिस्थितियों, उनके संदेशों, मां मरियम द्वारा सहे गए कष्टों के बारे में भजन गाते हैं। डोमेनिक ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत कष्टमय परिस्थितियों में हुआ। उनकी मां मरियम और उनके पालक पिता जोसफ जनगणना में नाम दर्ज कराने के लिए जा रहे थे।उन्होंने कहा कि इसी दौरान मां मरियम को प्रसव पीड़ा हुई लेकिन किसी ने उन्हें रूकने के लिए अपने मकान में जगह नहीं दी। अंततः एक दंपति ने उन्हें अपनी गौशाला में शरण दी जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। फादर डोमेनिक ने बताया कि भारत में भी यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर समेत समूचे पूर्वोत्तर भारत में लोग विशेषकर युवा बेहद उत्साह के साथ टोलियों में निकलते हैं और रात भर घर-घर जाकर कैरल गाते हैं।

उपहारों का आदान-प्रदान

लीजिए, क्रिसमस आ गया! प्रेम, करुणा, क्षमा और सद्भावना का संदेश देने वाले ईसा मसीह का जन्मदिन। यूं तो यह विश्व की एक तिहाई आबादी यानी ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन क्रिसमस का तिलस्म ईसाइयों तक सीमित नहीं है और क्यों नहीं, आखिर ईसा का संदेश देश, काल, समुदाय, संस्कृति की सीमाओं से परे है। यही कारण है कि क्रिसमस की धूम किसी न किसी रूप में दुनिया भर में मची रहती है। क्रिसमस सिर्फ ईसा के शाश्वत संदेश को याद करने व उनके जन्म की खुशियां मनाने के पर्व तक सीमित नहीं है। विश्व के कई देशों में यह वर्षभर का सबसे बड़ा आर्थिक उत्प्रेरक भी है। इनमें विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले अमेरिका, योरप के साथ-साथ अन्य कई देश भी शामिल हैं। जहां नुक्कड़ की दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल्स तक में क्रिसमस पर तमाम वस्तुओं की बिक्री सामान्य से कई गुना तक बढ़ जाती है। अनेक छोटी-बड़ी कंपनियां इस अवसर पर अपने नए उत्पाद लांच करती हैं। लुभावने सेल व डिस्काउंट योजनाएं तो होती ही हैं। बिक्री इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि लोग क्रिसमस पर केवल स्वयं के लिए ही खरीददारी नहीं करते बल्कि रिश्तेदारों, मित्रों, स्नेहियों को भेंट करने के लिए उपहार भी खरीदते हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को उपहार देने के लिए थोक में ऑर्डर देती हैं। क्रिसमस पर जमकर खरीददारी करते हैं और उपहारों का आदान-प्रदान भी करते ही हैं। पसंद न आने वाले उपहारों की आपस में अदला-बदली कर लेने का चलन भी काफी बढ़ गया है। आपको कहीं से मिला उपहार मुझे पसंद है और मुझे मिल गया है आपकी पसंद का उपहार, तो चलो एक्सचेंज कर लें। आप भी खुश, मैं भी खुश। उपहार देने वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ और दुकानदार तो खैर, माल बेचकर खुश है ही। चारों ओर खुशियां फैलाने से बेहतर क्या तरीका होगा क्रिसमस मनाने का!

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

राणा ने जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण का दिया आश्वासन

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुना।

संवाद के दौरान मंत्री ने पीएचई दैनिक वेतनभोगी संघ के प्रतिनिधियों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभाग से जुड़े ठेकेदारों, सामाजिक वानिकी विभाग के कर्मचारियों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की बातों को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। पीएचई दैनिक वेतनभोगी संघ के प्रतिनिधियों ने सेवाओं के नियमितीकरण, लंबित वेतन की रिहाई और अन्य सेवा संबंधी चिंताओं को उठाया। आई एंड एफसी विभाग के ठेकेदारों ने समय पर भुगतान, निविदा प्रक्रियाओं और विकास कार्यों के सुचारू निष्पादन से संबंधित मुद्दों को सामने रखा। सामाजिक वानिकी विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री को जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया और वानिकी एवं संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और शमन उपायों, वन संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन तथा मंत्री के पोर्टफोलियो के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों से संबंधित शिकायतों को भी उजागर किया। सभी प्रतिनिधिमंडलों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हुए राणा ने कहा कि उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की योग्यता के आधार पर जांच की जाएगी और समयबद्ध तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों पर तत्काल ध्यान देने और उनके शीघ्र निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

50 लाख रुपये की लागत से बनी जुथाना संपर्क सड़क का किया उद्घाटन

कठुआ, 24 दिसंबर (हि.स.)। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधायक राजीव जसरोटिया ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य स्थानीय निवासियों की आवागमन क्षमता और दैनिक जीवन को सुगम बनाना है।

उद्घाटन की गई पहली परियोजना जुथाना गांव को जुथाना पुल से जोड़ने वाली संपर्क सड़क थी, जो 500 मीटर लंबी है और 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित है। इसके बाद विधायक जसरोटिया ने 5 लाख रुपये की लागत से पूरी हुई सेसवां से रजनी एसटी बस्ती सड़क का उद्घाटन किया। हालांकि यह सड़क आकार में छोटी है लेकिन निवासियों के लिए इसका काफी महत्व है क्योंकि यह दैनिक आवागमन को सुगम बनाती है, सुरक्षा बढ़ाती है और पड़ोसी बस्तियों के बीच सामाजिक-आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देती है।

सभा को संबोधित करते हुए विधायक जसरोटिया ने सड़क के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि इससे सुगम परिवहन संभव होगा, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही बढ़ेगी और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अवसंरचना पहलें केवल कंक्रीट और डामर की संरचनाएं नहीं हैं बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए अवसर और प्रगति के मार्ग हैं। विधायक जसरोटिया ने जन-केंद्रित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक अवसंरचना पहल निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है। उद्घाटन समारोह में निवासियों, ग्राम बुजुर्गों और सामुदायिक नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जमीनी स्तर पर ठोस विकास प्रदान करने के लिए विधायक के निरंतर प्रयासों की सराहना की।

अटल जी को याद करते हुए जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। अटल स्मृति वर्ष अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू के अंबफल्ला के पास अटल चौक पर उनकी प्रतिमा की सफाई और माला चढ़ाकर पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति आजीवन समर्पण को याद करते हुए श्रद्धांजलि का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर भाजपा महासचिव (संगठन) अशोक कौल, महासचिव गोपाल महाजन, भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट के साथ किया गया।

पूर्णिमा शर्मा जिला अध्यक्ष जम्मू एडवोकेट। राजेश गुप्ता, प्रमोद कपाही, सुभाष गुप्ता, सुनीत रैना, और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। सम्मान स्वरूप प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट द्वारा किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए अशोक कौल ने कहा कि अटल स्मृति वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा ने कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के अमूल्य योगदान और स्थायी विरासत को याद करने और सम्मान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस से होगी।

सांबा पुलिस द्वारा अवैध खनन पर कार्रवाई, सात डंपर जब्त

सांबा, 24 दिसंबर (हि.स.)। सांबा जिले में अवैध खनन पर चल रही कार्रवाई के तहत सांबा पुलिस ने सांबा और घगवाल पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में सात डंपर जब्त किए हैं जिनका इस्तेमाल निर्माण सामग्री के अवैध परिवहन खनन के लिए किया जा रहा था। सांबा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सांबा पुलिस स्टेशन के सुपवाल, राख अंब तल्ली पुलिस चौकियों के प्रभारी और घगवाल पुलिस स्टेशन के राजपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त करते हुए पंजीकरण संख्या जेके21ज़जी-9749 जेके02सीजे-5591 जेके21एच-5888, जेके21जी-7817, जेके21डी-6431, जेके21बी-1526 और जेके21के-7385 वाले सात डंपर जब्त किए हैं जिनका उपयोग क्षेत्र में निर्माण सामग्री के अवैध परिवहन खनन के लिए किया जा रहा था। उपरोक्त वाहनों को सांबा पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सांबा भूविज्ञान एवं खनन विभाग को सौंप दिया है।

30,000 रुपये की रिश्वत पेशकश करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर, 24 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को जम्मू के दक्षिण शहर के पुलिस अधीक्षक को प्रदर्शनी-सह-बिक्री की तारीख बढ़ाने के संबंध में 30,000 रुपये की रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में उसके मालिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आज जारी एक बयान के अनुसार जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत एफआईआर संख्या 01/2024 के मामले में जम्मू स्थित विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधीश की माननीय अदालत में मेसर्स एशियन एसोसिएट्स के मालिक चंदर शेखर वोहरा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। उन पर जम्मू के दक्षिण शहर के पुलिस अधीक्षक को गांधी नगर स्थित गोल मार्केट में प्रदर्शनी-सह-बिक्री की तारीख बढ़ाने के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है।

बयान में कहा गया है कि यह मामला जम्मू के पुलिस स्टेशन एसीबी में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिटी साउथ, जम्मू द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उपर्युक्त व्यक्ति ने गोल मार्केट, गांधी नगर, जम्मू में प्रदर्शनी सह बिक्री की तारीख बढ़ाने के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क किया और इसके बदले में 30,000 रुपये की रिश्वत देने का प्रयास किया। जांच के दौरान एक टीम गठित की गई और आरोपी शेखर वोहरा, जो मेसर्स एशियन एसोसिएट्स के मालिक हैं, को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की पेशकश करते हुए एसपी सिटी साउथ, जम्मू के कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की रकम भी स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके से बरामद कर जब्त कर ली गई। मामले की जांच पूरी होने के बाद जैसा कि सिद्ध हो चुका है, उक्त आरोपी के खिलाफ न्यायिक निर्णय के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय, जम्मू में 24-12-2025 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

जम्मू के दो युवा रूसी सेना में भर्ती, संपर्क सितंबर 2025 से टूटा

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू के दो युवाओं को रूसी सेना में भर्ती किए जाने के बाद उनके परिवारों का उनसे सितंबर 2025 से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिवारों ने बताया कि युवाओं के आगे की स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले ने उनके घरों में चिंता और तनाव बढ़ा दिया है। परिवार अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं से उनके हालात के बारे में जानकारी देने की मांग कर रहे हैं।

आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

कठुआ, 24 दिसंबर (हि.स.)। कठुआ प्रशासन ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन, समन्वय और संचालन पर जिला अधिकारियों के लिए मॉक ड्रिल-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम डीएसपी रघुबीर सिंह के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) टीम के समन्वय से आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ विश्वजीत सिंह ने की। आरटीओ कठुआ सुरिंदर शर्मा, एसीडी अखिल सडोत्रा, सीएमओ डॉ. विजय रैना, अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारी और उपायुक्त कार्यालय परिसर के कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सत्र के दौरान डीएसपी रघुबीर सिंह ने आपात स्थितियों के दौरान समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया के प्रति अधिकारियों को जागरूक किया और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए अंतर-विभागीय समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश की घटनाओं के दौरान एसडीआरएफ की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही प्रतिभागियों को प्राथमिक चिकित्सा, निकासी प्रक्रियाओं और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए एडीसी कठुआ विश्वजीत सिंह ने आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी स्तरों पर परिचालन तत्परता और तैयारी के महत्व पर जोर दिया।

शोपियां के चेक कीगम में रेलवे भूमि सीमांकन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। शोपियां जिले के चेक कीगम और आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों ने प्रस्तावित रेलवे परियोजना के लिए भूमि सीमांकन के खिलाफ मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों और जमीन मालिकों ने कहा कि सर्वे टीमों ने उत्पादक कृषि भूमि पर पोल और मार्कर लगाना शुरू कर दिया है, जबकि उनसे कोई पूर्व परामर्श या अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम उन लोगों के लिए गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, जो पूरी तरह से खेती और बागवानी पर निर्भर हैं।

प्रदर्शनकारियों ने स्लोगन और पोस्टर के जरिए अधिकारियों पर फ़सहानुभूति रहित विकासफ़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं रोजगार देने या किसानों के हित सुरक्षित करने के बजाय स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित रेलवे लाइन कई दशकों से मेहनत और निवेश से विकसित उच्च उत्पादकता वाले सेब के बागों और धान के खेतों से होकर गुजर रही है।

इस दौरान शोपियां के विधायक शबीर अहमद कुल्ले मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की चिंताओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो किसानों को नुकसान पहुँचाए या बेरोजगार करे।

नेहा जैन जम्मू-कश्मीर में सेवा देने वाली अपनी बैच की एकमात्र अधिकारी

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है, जिनमें वर्तमान में बारामुला, जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात नेहा जैन भी शामिल हैं नेहा जैन अपनी बैच की एकमात्र आईपीएस अधिकारी हैं, जो जम्मू-कश्मीर में सेवा दे रही हैं और पदोन्नति प्राप्त की हैं। अन्य पदोन्नत अधिकारियों में अनुराग दारू, जिन्होंने पहले जम्मू-कश्मीर में सेवा की और यूनियन टेरीटरी में अपने प्रशिक्षण का एक हिस्सा पूरा किया, अक्षत आयुष, आकांक्षा मिलिंद तामगड़े और आशिष कुमार शामिल हैं।

जम्मू अनाज मंडी वेयरहाउस में मजदूरों और पुलिस के बीच विवाद

जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के जम्मू जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया, जब एक मजदूर पर पुलिस पोस्ट के कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप लगा।

घटना के बाद मजदूरों में भारी रोष फैल गया और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल कर दी। सभी मजदूर वेयरहाउस पुलिस पोस्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जम्मू साउथ के डीएसपी और गांधी नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लेबर संगठन के प्रधान को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेयरहाउस एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रशासन गाँव की ओर के छठे दिन जिले में कई व्यापक जनसंपर्क अभियान आयोजित

कठुआ, 24 दिसंबर (हि.स.)। प्रशासन को जनता के घर तक पहुंचाने के लिए जारी जनसंपर्क पहलों के तहत कठुआ जिले के विभिन्न ब्लॉकों और उपमंडलों में प्रशासन गाँव की ओर शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावी जनसंपर्क, शिकायत निवारण और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित हुई।

ऐसा ही एक जनसंपर्क शिविर बुधवार को नगरोटा गुजरू ब्लॉक के पंचायत घर दानजसधर में बिलवार के अतिरिक्त उपायुक्त विनय खोसला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में तहसीलदार रामकोट जीतिंदर सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान जनता की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना गया, मौके पर ही सेवाएं प्रदान की गईं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई गई, जिससे सहभागी शासन के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को बल मिला। इसी तरह की एक पहल के तहत हीरानगर तहसील के मेला गांव में एक जनसंपर्क शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हीरानगर के विधायक विजय कुमार शर्मा और हीरानगर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट फुलैल सिंह उपस्थित थे। शिविर के दौरान जनता ने जल आपूर्ति, जेजेएम योजनाओं के कार्यान्वयन, कर्मचारियों की कमी, पीएमएवाई (जी), अतिक्रमण और स्थानीय बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे उठाए। लाभार्थियों को एसएमएएस और आईएनजीओएपी के तहत स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। एक अन्य जनसंपर्क शिविर बसोहली तहसील के नियाबत भूंड के जंद्राल्ली गांव में नियाबत भूंड के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे नायब तहसीलदार द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में जनता की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें लोगों की शिकायतें सुनी गईं और मौके पर ही कई सेवाएं प्रदान की गईं। इसी प्रकार बनी उप-मंडल में भी एक जनसंपर्क शिविर का आयोजन किया गया, जिससे प्रशासन की पहुंच दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित हुई।

श्रीनगर के डीसी ने जिले में पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की

श्रीनगर, 24 दिसंबर(हि.स.)। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले भर में सोलर रूफटॉप लगाने में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए योजना की निगरानी और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उप आयुक्त श्रीनगर अक्षय लबरू ने आज डीसी कार्यालय परिसर के बैठक कक्ष में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य योजना अधिकारी फैयाज अहमद डार, केपीडीसीएल के कार्यकारी इंजीनियर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (बैंक) के अलावा बैठक में केपीडीसीएल के इंजीनियर और सूचीबद्ध योजना विक्रेता भी उपस्थित थे जिन्होंने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चल रहे स्थापना कार्यों और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का टीमवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया।

शुरुआत में डीसी ने श्रीनगर के सभी चार विद्युत डिवीजनों में प्राप्त लक्ष्यों प्राप्त आवेदनों और पूर्ण की गई स्थापनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिवीजनवार और टीमवार प्रदर्शन का विस्तृत आकलन किया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को समयबद्ध तरीके से सभी पात्र परिवारों तक पहुंचने पर जोर दिया ताकि उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें।

UNION TERRITORY OF Jammu & Kashmir
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
JAL SHAKTI DEPARTMENT MECHANICAL DIVISION
RTIC, JAMMU
Ph. 0191-2956288

NOTICE

Subject:- This Office E - Nit 38 of 2025-26dated :-05.12.2025.

E - Nit 38 of 2025-26dated :-05.12.2025 floated under endorsement number MDJ/RTIC/1268-71 Dated 05.12.2025 for Replacement of old existing 55 No.s x 2 volt cells, 110 Volt, 100AH sealed maintenance free battery banks with new one for providing DC power supply to VCB's/ HT panels as safety equipment for 750 KW slip ring induction motors installed at TPH, Jammu stand cancelled due to Inadequate Confirmatory documents.

No.: MDJ/RTIC/1401-04 Dated: 23.12.2025

No:DIP/J-9335/25
Dtd:24-12-2025

Sd/-
Executive Engineer,
Mechanical Division,
RTIC, Jammu

एसएसपी डोडा ने सीएपी-2025 के तहत गंदोह में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की अध्यक्षता की

डोडा, 24 दिसंबर (हि.स.)। सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) 2024-25 के तहत डोडा पुलिस ने हेलीपैड ग्राउंड, गंडोह में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जो 21 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

एसएसपी डोडा श्री समापन समारोह में जेकेपीएस के संदीप मेहता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन श्री की देखरेख में किया गया। लव करण, एस.डी.पी.ओ गंदोह, जिन्होंने टूर्नामेंट के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी काम किया और भाग लेने वाली टीमों का स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम गंदोह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए एसएसपी डोडा ने खिलाड़ियों और आयोजकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए सराहना की और दोहराया कि डोडा पुलिस युवाओं के बीच सकारात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नियमित रूप से खेल और समुदाय-उन्मुख कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उप-मंडल स्तर पर ऐसी खेल गतिविधियां युवा प्रतिभाओं के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करती हैं और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने में मदद करती हैं।

एसएसपी डोडा ने युवाओं से एक शांतिपूर्ण, अपराध मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

टूर्नामेंट में उपमंडल गंदोह से कुल 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच वाली क्रिकेट क्लब, गंदोह और लायंस क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया जिसमें वाली क्रिकेट क्लब विजेता रहा।

इस अवसर पर विजेता टीम को 25,000 का नकद पुरस्कार दिया गया जबकि उपविजेता टीम को 15,000 के साथ-साथ ट्रॉफी और भागीदारी प्रमाण पत्र भी दिए गए। एक बड़ी भीड़ ने फाइनल मैच देखा और इस तरह की युवा-केंद्रित खेल पहल के आयोजन में डोडा पुलिस के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की।

बाद में दिन में एसएसपी डोडा संदीप मेहता, जेकेपीएस ने गोवारी किल्होट्रान में एक पुलिस-सामुदायिक भागीदारी समूह (पीसीपीजी) की बैठक भी आयोजित की। बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बातचीत के दौरान उठाए गए सार्वजनिक मुद्दों को एसएसपी ने धैर्यपूर्वक सुना जिन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस से संबंधित मामलों को तुरंत हल किया जाएगा जबकि अन्य विभागों से संबंधित मुद्दों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

आईजीपी कश्मीर ने 26वें राष्ट्र कथा शिविर के लिए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को गुजरात के लिए रवाना किया

श्रीनगर, 24 दिसंबर(हि.स.)। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बर्डी-आईपीएस ने वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा गांव प्रांसला, उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात में आयोजित 26वें राष्ट्र कथा शिविर में भाग लेने के लिए छात्रों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।ध्वजारोहण समारोह जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में आयोजित किया गया था और जोनल पुलिस मुख्यालय कश्मीर द्वारा आयोजित किया गया था। कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों से कुल 22 छात्र तीन कार्यवाहकों के साथ 27 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक निर्धारित शिविर में भाग लेंगे। फ्लैग ऑफ समारोह में डीआइजी सीकेआर श्रीनगर राजीव पांडे-आईपीएस, एसएसपी श्रीनगर डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती-आईपीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छात्रों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान आईजीपी कश्मीर ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और धार्मिक सद्भाव और समग्र व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में ऐसे प्रदर्शन कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को नए मूल्यों को सीखने, विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने और स्थायी यादें बनाने के द्वारा इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

जोनल पुलिस मुख्यालय कश्मीर ने प्रतिभागियों के लिए भोजन और आवास सुविधाओं सहित व्यापक व्यवस्था की थी। प्रत्येक छात्र को यात्रा और ठहरने के दौरान आराम सुनिश्चित करने के लिए कपड़ों और आवश्यक वस्तुओं से युक्त एक अनुकूलित किट भी प्रदान की गई है।

श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित 26वें राष्ट्र कथा शिविर का उद्देश्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करके युवाओं का पोषण करना और प्रख्यात वक्ताओं द्वारा आयोजित प्रेरक और मूल्य-आधारित सत्रों के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना है।

कश्मीर संभागीय आयुक्त ने शिक्षण संस्थानों में स्थानीय नशामुक्ति तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया

श्रीनगर, 24 दिसंबर (हि.स.)। संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने बुधवार को घाटी में बढ़ते मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए संभागीय आयुक्त ने विद्यालयों और महाविद्यालयों सहित शिक्षण संस्थानों को अपने-अपने परिसरों में स्थानीय नशामुक्ति तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक पुरुष और एक महिला नोडल अधिकारी को नामित करे जो सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के कार्यान्वयन, छात्र परामर्श,

कमजोर व्यक्तियों की पहचान और प्रभावित छात्रों की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होंगे।

वक्फ अधिकारियों को धार्मिक नेताओं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया ताकि वे समाज में अपने प्रभाव का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकें और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकें।

कोचिंग संस्थानों और छात्र आवासों के संबंध में आईएमएचएएनएस को कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए एक संरचित निगरानी ढांचा विकसित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों का एक मजबूत समूह तैयार करना था।

संपादकीय

प्रशासनिक देरी जानलेवा साबित हो रही है

जम्मू के पाँच प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से तीन में सीटी स्कैन मशीनों का लंबे समय से खराब पड़ा रहना सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में प्रशासनिक उदासीनता और गलत प्राथमिकताओं की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। सीटी स्कैन जैसी जांच सुविधाएँ कोई विलासिता नहीं, बल्कि समय पर और सटीक इलाज के लिए अनिवार्य साधन हैं। इसके बावजूद जम्मू के मरीजों को महीनों—और कुछ मामलों में एक वर्ष से भी अधिक समय तक—इस बुनियादी सुविधा से वंचित रखा गया है।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, श्री महाराजा गुलाब सिंह (एसएमजीएस) अस्पताल और चेस्ट डिज़ीज़ अस्पताल जैसे संस्थान न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, प्रसूति और टीबी उपचार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों का चालू न होना मरीजों को जीएमसी जम्मू और बोन एंड जॉइंट अस्पताल जैसे पहले से ही अत्यधिक दबाव में चल रहे संस्थानों के चक्कर लगाने को मजबूर कर रहा है। नतीजतन, लंबी प्रतीक्षा अवधि आम हो गई है, जो रेफरल-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली के उद्देश्य को ही विफल कर देती है।

इस विफलता की मानवीय कीमत बहुत भारी है। मरीजों और उनके परिजनों को बार-बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वह भी गंभीर चिकित्सकीय स्थितियों में। कई लोगों के पास निजी क्लीनिकों में महंगे डायग्नोस्टिक परीक्षण कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे उन परिवारों पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ता है जो सरकारी अस्पतालों पर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि वे निजी इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस तरह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विफलता आर्थिक अन्याय में बदल जाती है।स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाता है प्रशासन की ओर से तत्परता का अभाव। अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि खरीद प्रक्रिया चल रही है, देरी लगातार बनी हुई है। कुछ अस्पतालों के लिए अभी तक मंजूरियाँ लंबित होना प्रणाली में समन्वय और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। जब हजारों लोगों की सेवा के लिए बनी मशीनें महीनों तक बंद पड़ी रहती हैं, तो दिए गए स्पष्टीकरण खोखले लगते हैं। तत्काल खरीद से आगे, यह संकट स्वास्थ्य योजना में एक गहरी संरचनात्मक खामी को उजागर करता है। निवारक रखरखाव अनुसूचियों, वैकल्पिक व्यवस्थाओं और उपकरणों की अतिरिक्त व्यवस्था (रेडंडेंसी) का अभाव बताता है कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन रणनीतिक के बजाय प्रतिक्रियात्मक ढंग से किया जा रहा है। आवश्यक डायग्नोस्टिक उपकरणों को कभी भी पूरी तरह ठप होने की स्थिति तक नहीं पहुँचने देना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी अस्पताल आबादी के लिए जीवनरेखा हैं।

साथ ही, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि महत्वपूर्ण मशीनें इतने लंबे समय तक क्यों खराब पड़ी हैं, देरी के लिए कौन जिम्मेदार है और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नियमित सार्वजनिक खुलासे, समयबद्ध मरम्मत या प्रतिस्थापन की समय-सीमाएँ और स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली में भरोसा बहाल करने में मदद कर सकते हैं। जवाबदेही के बिना, ऐसी विफलताएँ सामान्य बन सकती हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कमजोर होगा और मरीजों को पहले से ही महंगे और असमान निजी क्षेत्र की ओर धकेला जाएगा। स्वास्थ्य प्रशासन का मूल्यांकन बयानों से नहीं, बल्कि परिणामों से होना चाहिए। अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, उचित रखरखाव अनुबंध सुनिश्चित करने चाहिए और इतने लंबे व्यवधानों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। डायग्नोस्टिक सेवाएँ आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ हैं, और उनकी उपेक्षा पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र को कमजोर करती है।

जम्मू के मरीज बहानों और अंतहीन प्रतीक्षा से बेहतर के हकदार हैं। सीटी स्कैन सेवाओं की शीघ्र बहाली केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि एक नैतिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्व है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 संरचनात्मक कमियों को दूर करता है

विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, समन्वय और पारदर्शिता हो सके — न कि स्थानीय प्राथमिकताओं को दबाने के लिए। केंद्रित किया गया है सिर्फ व्यवस्था और सामंजस्य को, निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ही रहेगा। इस तरह यह कानून बिखराव को ठीक करता है, विकेंद्रीकरण को कमज़ोर नहीं करता। यह आरोप भी सही नहीं है कि इस सुधार को बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया गया। इस विधेयक से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, तकनीकी कार्यशालाएँ और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं।

श्री शिवराज सिंह चौहान

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंज़ूरी दी है। यह कानून वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिनकरता है और सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और व्यापक वितरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, ताकि ग्रामीण भारत मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके। सुधारों की गलत व्याख्या वीबी- जी राम जी अधिनियम लागू होते ही कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, जो गहराई से देखने पर सही नहीं ठहरतीं। कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी कमजोर कर दी गई है, विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को बिना परामर्श के कमज़ोर किया गया है और यह सुधार असल में राजकोषीय खर्च घटाने का तरीका है, जिसे ढांचे में बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन ये सभी दावे इस कानून के असली उद्देश्य और प्रावधानों को ठीक से न समझ पाने के कारण किए जा रहे हैं। इस गलतफहमी का मूल कारण एक गहरी वैचारिक त्रुटि है- यह मान लेना कि कल्याण और विकास एक दूसरे के विरोधी विरोधी विकल्प हैं। नया ढांचा इसके बिल्कुल उलट सोच पर आधारित है ः कल्याण, जो कि वैधानिक आजीविका गारंटी को मजबूत करने पर केंद्रित है, और विकास, जो कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है, परस्पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आय सहायता, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और लंबे समय की ग्रामीण उत्पादकता को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि कानूनी संरचना में ही शामिल सोच है। यह कहना कि कानूनी रोजगार अधिकार कमजोर कर दिया गया है, सही नहीं है। इस कानून में रोजगार गारंटी का वैधानिक और न्यायिक अधिकार बरकरार रखते हुए उसे और मजबूत किया गया है। अधिकार घटाने के बजाय इसे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहले जो प्रक्रियागत शर्तें बेरोजगारी भत्ता मिलने में रुकावट बन जाती थीं, उन्हें हटा दिया गया है और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। यह सुधार लंबे समय से मौजूद उस अंतर को दूर करने का प्रयास है, जो कागज़ पर किए गए वादे और लोगों के धरातल के अनुभव के बीच था। यह भी कहा जा रहा है कि मांग-आधारित रोजगार छोड़कर ऊपर से थोपे गए योजनागत मॉडल को लागू कर दिया गया है। यह भी एक गलत धारणा है। काम की मांग पहले की तरह ग्रामीण मजदूरों से ही आती है। फर्क यह है कि अब काम तभी शुरू नहीं किया जाएगा जब मजबूरी या संकट बढ़ जाए, बल्कि पहले से ही भागीदारी आधारित ग्राम-स्तरीय योजना बनाकर तैयारी कर ली जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब मजदूर काम मांगें, तो उनके लिए तुरंत काम उपलब्ध हो, और प्रशासनिक तैयारी न होने के कारण उन्हें मना न किया जाए। इस तरह योजना बनाना मांग को दबाता नहीं, बल्कि उसे सही रूप से लागू करता है। केंद्रीकरण का आरोप इस कानून की पूरी संरचना को नज़रअंदाज़ करता है। ग्राम पंचायतें पहले की तरह ही योजना बनाने और लागू करने की प्रमुख संस्था बनी रहती हैं और ग्राम सभाओं के पास स्थानीय योजनाओं को मंज़ूरी देने का अधिकार यथावत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब विकेंद्रीकरण बिना व्यवस्था के या कभी-कभार होने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि एक नियमित, व्यवस्थित और सहभागी प्रणाली के रूप में होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, समन्वय और पारदर्शिता हो सके — न कि स्थानीय प्राथमिकताओं को दबाने के लिए। केंद्रित किया गया है सिर्फ व्यवस्था और सामंजस्य को, निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ही रहेगा। इस तरह यह कानून बिखराव को ठीक करता है, विकेंद्रीकरण को कमज़ोर नहीं करता। यह आरोप भी सही नहीं है कि इस सुधार को बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया गया। इस विधेयक से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, तकनीकी कार्यशालाएँ और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं। गांव-स्तरीय योजना संरचना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय की व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम जैसे प्रमुख प्रावधान राज्यों से मिले सुझावों और वर्षों के अनुभव से सीखे गए सबक के आधार पर तैयार किए गए हैं। आवंटन में वृद्धि, समानता यह धारणा भी तथ्यों से मेल नहीं खाती कि पिछले दशक में रोजगार गारंटी को लगातार कमजोर किया गया। बजट आवंटन 2013-14 के 33,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2,86,000 करोड़ हो गया। 2013-14 तक कुल 1,660 करोड़ मानव-दिवस के बदले अब तक 3,210 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ। केंद्र से जारी धनराशि 2.13 लाख करोड़ से बढ़कर 8.53 लाख करोड़ हो गई और पूरे हुए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख तक पहुँच गए। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 56.73% हो गई। अब 99% से अधिक फंड ट्रांसफर आदेश समय पर जारी होते हैं और लगभग 99% सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हैं। ये सभी रुझान उपेक्षा नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर प्रदर्शन को दिखाते हैं। लेकिन समय के साथ यह भी साफ हो गया कि पुराने ढांचे में खुद कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं-जैसे बीच- बीच में ही काम मिलना, बेरोजगारी भत्ता लागू कराने की कमजोर व्यवस्था, बिखरे हुए और असंगठित तरीके से संपत्ति/संसाधन निर्माण, और दोहराव व फर्जी प्रविष्टियों की गुंजाइश। ये कमजोरियां सूखे के समय, बड़े पैमाने पर पलायन के दौर में और कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान जमीन पर साफ दिखाई दीं। नए कानून के तहत की गई वित्तीय व्यवस्था को भी गलत तरीके से सरकारी जिम्मेदारी छोड़ने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सच यह है कि केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है। केंद्र का हिस्सा 86,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 2,95,000 करोड़ तक हो रहा है, जो ग्रामीण रोजगार के प्रति मजबूत और बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। 60:40 की फंडिंग व्यवस्था वैसे ही है जैसी अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में वर्षों से लागू है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90ः10 का अलग अनुपात रखा गया है। इसलिए यह किसी तरह की वित्तीय पीछे हटने का संकेत नहीं,बल्कि साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को और मजबूत करने का संकेत है। न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए धन आवंटन नियमों के आधार पर किया जाता है, और राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए नियमों में दिए गए स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ मानदंडों का पालन किया जाता है। राज्यों को सिर्फ लागू करने वाली एजेंसियों की तरह नहीं, बल्कि विकास के भागीदार के रूप में देखा गया है, जिन्हें कानूनी ढांचे के भीतर अपनी योजना अधिसूचित करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है। लचीलापन भी बरकरार रखा गया है- प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थितियों में राज्य अतिरिक्त छूट, अधिक प्रकार के कार्य और अस्थायी रूप से रोजगार बढ़ाने जैसी सिफारिशें कर सकते हैं। इस तरह नियम-आधारित आवंटन और परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन, दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सहकारी संघवाद को मजबूत किया गया है। यह कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे पहले से ही एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि तय कर सकें, जो बुआई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसमों को कवर करे, और उन दिनों के दौरान काम न कराया जाए। यह घोषणा ज़िला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर, स्थानीय मौसम और कृषि परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ी हुई रोजगार गारंटी कृषि कार्यों में बाधा न बने, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर चले। यूपीए का रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि राज्य सरकारें इस योजना के तहत मनमाने ढंग से काम कर रही थीं यह स्वीकारोक्ति अपने आप में शासन की एक गंभीर विफलता दिखाती हैः कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी ही राज्य सरकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी, जिसके कारण मनरेगा में दुरुपयोग, फर्जी जॉब कार्ड और वित्तीय गड़बड़ियां जैसी समस्याएं पैदा हो गईं। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता लगातार कमजोर होती गई। 2010-11 में 2,40,100 करोड़ के बजट को घटाकर 2012-13 तक सिर्फ 33,000 करोड़ कर दिया गया, जबकि राज्यों की ओर से मांग बढ़ रही थी। 2013 में संसद में दिए गए जवाब में तत्कालीन राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने माना कि मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों की संख्या 2010-11 के 7.55 करोड़ से घटकर नवंबर 2013 तक सिर्फ 6.93 करोड़ रह गई। धन जारी करने में देरी, भुगतान में पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक उदासीनता ने मजदूरों को काम मांगने से हतोत्साहित किया, जिससे कानून में दी गई रोजगार गारंटी कमजोर पड़ गई। महालेखा परीक्षक (कैग) की 2013 की रिपोर्ट ने यूपीए के समय मनरेगा की असल स्थिति उजागर कर दी। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन सामने आया- 4.33 लाख से ज्यादा फर्जी या गलत जॉब कार्ड, हजारों करोड़ रुपये बिना हिसाब के निकासी और अनियमित कामों में गंवाए गए, 23 राज्यों में मजदूरी का भुगतान देर से हुआ या रोका गया, और देश की आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सही रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब हैं- बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वे अपने आवंटित धन का केवल लगभग 20त्न ही खर्च कर पाए। यानी योजना वहीं नाकाम रही, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल्याण और विकास के बीच चयन के रूप में बहस को प्रस्तुत करना गलत है। जब कल्याण मजबूत रोजगार गारंटी पर आधारित हो और विकास टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे और उत्पादकता पर आधारितहो, तो ये एक-दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक-दूसरे पर निर्भर हैं। असली निर्णय यह था कि क्या उस ढांचे को स्थिर रखा जाए जो अक्सर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था, या इसे एक आधुनिक, लागू करने योग्य और एकीकृत रोजगार गारंटी प्रणाली में सुधारा जाए जो विकास के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा दे। नया कानून रोजगार का कानूनी अधिकार बनाए रखता है, अधिकारों को बढ़ाता है, श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करता है और वर्षों के कार्यान्वयन में सामने आई संरचनात्मक कमजोरियों को ठीक करता है। यह विनाश नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित नवीनीकरण की प्रक्रिया है।

(लेखक भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं।)

अटल बिहारी वाजपेयी : लोकतांत्रिक नेतृत्व के आदर्श पुरुष

-गिरीश्वर मिश्र

स्वतंत्र भारत में यहाँ की विराट सांस्कृतिक परम्परा के संधान और उन्मेष की मानसिकता संजोने वाले जन-नायकों में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी निश्चय ही अनूठे व्यक्तित्व हैं। वह बिना किसी पूर्वाग्रह के पक्ष हो या विपक्ष, वाम हो या दक्षिण, केंद्र हो या परिधि सब प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। लोकाभिमुख होने की यह वृत्ति प्रचारक के रूप में उनकी लम्बी देश-साधना के दौरान विकसित हुई थी। साथ ही संपादन कार्य उनको अद्यतन करता रहा। इस क्रम की ही परिणति थी कि भारतीय संस्कृति की साधना के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।

आधुनिक मन वाले वाजपेयी जी ने आगे बढ़ कर देश की व्यापक कल्पना को संकल्प, प्रतिज्ञा और कर्म से जोड़ा और समर्पण के लिए आवाहन किया।

स्मरणीय है कि भारत पर अंग्रेजी औपनिवेशिक राज की लम्बी दासता से मुक्ति मिलने के बाद आज लोकतांत्रिक देशों की प्रथम पंक्ति में वैश्विक क्षितिज पर भारत आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से एक सशक्त देश के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। इस विरल उपलब्धि के पीछे राष्ट्रीय नेतृत्व और रीति-नीति की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने विभाजन के बाद की कठिन परिस्थितियों में साल 1947 में एक आधुनिक और समाजवादी रुझान के साथ उत्तर उपनिवेशी स्वतंत्र भारत की यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में जिस ढांचे को लेकर हम आगे बढ़े वह अपने बौद्धिक गठन में बहुत हद तक अंग्रेजों द्वारा अपने उपनिवेश के लोगों के लिए खड़ा किया था। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में नवाचार जरूर शुरू हुए और पंचवर्षीय विकास योजनाओं का दौर भी चला ताकि देश विकास की दौड़ में विकासशील देशों से पीछे न रह जाय।

पर असंतोष भी बढ़ा जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की अगुआई में देश में व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा और भारत में सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तन की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की उपेक्षा जैसे प्रश्नों से उलझते राजनीति का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। संभ्रांत के वर्चस्व की जगह व्यापक समुदाय जिसमें हाशिए पर स्थित मध्यम और दलित वर्ग भी शामिल था राजनीति में प्रतिभागी बन कर अपनी प्रभावी भूमिका के लिए अग्रसर हुआ। वाजपेयी जी ने देश के लिए व्यापक परिवर्तन की आकांक्षा को इन शब्दों में रेखांकित किया- आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाक़ी हैं, रावी की शपथ अधूरी है।

भारतीय राजनीति के नए दौर में पारदर्शिता, साझेदारी और संवाद की ख़ास भूमिका रही। लोकतंत्र के लिए आपातकाल बड़ा आघात था। उसके बाद कांग्रेस के विकल्प के रूप में 'जनता दल' का गठन हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। वाजपेयी ने इस सरकार में परराष्ट्र मंत्री का दायित्व संभला। आगे चलकर भारत का राजनैतिक परिदृश्य इस अर्थ में क्रमशः जटिल होता गया। यह स्पष्ट होने लगा कि विभिन्न राजनैतिक दलों को साथ लेकर चलने वाली एक समावेशी दृष्टि ही कारगर हो सकती थी। इसके लिए सहिष्णुता, खुलेपन की मानसिकता, सबको साथ ले चलने की क्षमता, सुनने-सुनाने का धैर्य और युगानुरूप सशक्त तथा दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। इन सभी कसौटियों पर एक सर्वमान्य नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ही खरे उतरे। विविधता भरी राजनीति में उनको लेकर बनी सहमति का ही परिणाम था कि भारतीय संसद में उनको तीन बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार किया गया। यह अनूठी घटना थी। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (नेशनल डेमोक्रेटिक अलाएंस या एनडीए) के कठिन नेतृत्व की कमान संभालते हुए वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने। गठबंधन वाली यह पहली पूर्णकालिक सरकार थी।

एनडीए में दो दर्जन के करीब राजनैतिक दल साथ आये थे और 81 मंत्री थे। इन सबको साथ लेकर चलना कठिन चुनौती थी जिसे वाजपेयी जी ने स्वीकार किया था और उस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। इनमें कुछ का उल्लेख प्रासंगिक होगा। उन्हीं की पहल पर भारत के चारों कोनों को सड़क से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई जिसके तहत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। संरचनात्मक ढाँचे के लिये कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि गठित किए गए।

विकसित भारत का कृषि मॉडल- गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन

राजेन्द्र शुक्ल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास के उस मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। इसी समग्र दृष्टि के अंतर्गत भारतीय कृषि को भी एक नए युग की ओर ले जाया जा रहा है। कृषि सदियों से हमारी सभ्यता की रीढ़ रही है। आधुनिक युग में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता ने खेती की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता, उसकी जलधारण क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, हमारे भोजन की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भारतीय कृषि की मूल आत्मा से जुड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सह-अस्तित्व और संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें गौमाता की भूमिका केंद्रीय रही है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा का आधार रही हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि गौवंश का संरक्षण सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गोबर और गोमूत्र से भूमि को पोषण मिलता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और मिट्टी पुनः जीवंत होती है। स्वस्थ मिट्टी से प्राप्त अन्न अधिक पौष्टिक, सुरक्षित और मानव शरीर के अनुकूल होता है।

प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि में प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की भारतीय पद्धति है। वे इसे किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और उन्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करने का सशक्त माध्यम मानते हैं। साथ ही, यह देशवासियों को रसायन-मुक्त, विषरहित भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग है। यही कारण है कि प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है।

प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली सरल, स्वदेशी और प्रभावशाली है। इसमें गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि कृषि आदानों के उत्पादन के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे प्राकृतिक इनपुट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और भूमि की उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाते हैं। पलवार (मल्चिंग) जैसी तकनीकें मिट्टी की नमी बनाए रखती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों की रक्षा करती हैं। इन उपायों से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे शून्य बजट प्राकृतिक खेती का लक्ष्य व्यवहारिक रूप से संभव होता है।

सहकारिता से समृद्धि और संस्थागत शक्ति

प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विजन सहकारिता से समृद्धि के तहत, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को संगठित किया जा रहा है एवं किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को न केवल सस्ती दरों पर प्राकृतिक खाद-बीज मिल सकें, बल्कि उनके विषमुक्त उत्पादों को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और सहकारिता का मेल ही ग्रामीण समृद्धि का नया मार्ग है।

प्राकृतिक खेती का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं है; इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य और जीवनशैली से है। आज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका एक बड़ा कारण रासायनिक अवशेषों से युक्त भोजन है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त शुद्ध और विषमुक्त अन्न पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

प्रधानमंत्री द्वारा योग और आयुष को वैश्विक पहचान दिलाना इसी समग्र स्वास्थ्य दृष्टि का हिस्सा है। योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या तभी पूर्ण लाभ देती है जब भोजन भी शुद्ध और प्राकृतिक हो। प्राकृतिक खेती, स्वस्थ भोजन और योग—तीनों मिलकर स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं।

प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का व्यावहारिक मंत्र—'एक एकड़, एक मौसम'—किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है। छोटे स्तर पर प्रयोग कर किसान बिना जोखिम उठाए परिणाम देख सकता है और फिर धीरे-धीरे विस्तार कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, आदानों की उपलब्धता और बाजार से जोड़ने के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठन इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक शक्ति प्राप्त हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि महिला किसान इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

इस संपूर्ण प्रयास में गौ-सेवा का स्थान केंद्रीय है। गौवंश का संरक्षण और संवर्धन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की दृष्टि में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी की इस दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती, गौ-संवर्धन और किसान कल्याण को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मिट्टी, किसान और उपभोक्ता—तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती केवल कृषि सुधार की पहल नहीं, बल्कि भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण है। गौमाता और मिट्टी की रक्षा के अपने सांस्कृतिक दायित्व को निभाते हुए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भोजन, संतुलित जीवनशैली और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित, आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने का सशक्त मार्ग है।

(लेखक, मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं।)

भारत ने श्रीलंका को फिर हराया, टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त

एजेंसी

विशाखापत्तनम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने पहला टी20 भी 8 विकेट से अपने नाम किया था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंका को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन तक सीमित कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। श्रीलंका की ओर से हर्षिता समरविक्रमा ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए, जबकि कप्तान चामरी अथापथु ने 31 रन की पारी खेली। हसीनी परेरा ने 22 रन का योगदान दिया, लेकिन शीर्ष और मध्यक्रम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। भारत की ओर से वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही। ओपनर शैफाली वर्मा ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 202 से अधिक के स्ट्राइक रेट से नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। स्मृति मंधाना ने 14 रन बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 26 रनों की तेज पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 10 रन जोड़े। भारत ने 11.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

खेल मंत्रालय ने शुरू की व्यापक इंटर्नशिप नीति, खेल पेशेवरों की नई पीढ़ी तैयार करने की पहल

नई दिल्ली। भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने व्यापक इंटर्नशिप नीति की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को खेल प्रशासन, खेल विज्ञान और खेल शासन से जुड़े क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव देकर भविष्य के दक्ष खेल पेशेवरों को तैयार करना है। इस नई नीति के तहत हर वर्ष 452 इंटर्नशिप प्रदान की जाएंगी। ये इंटर्नशिप मंत्रालय के साथ-साथ इसके प्रमुख स्वायत्त संस्थानों भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में उपलब्ध होंगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को खेल प्रशासन और उससे जुड़े पेशेवर क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।

देशभर से 127 से ज्यादा टीमों की एंट्री, हरीश शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप को लेकर उत्साह चरम पर

नई दिल्ली। भारत में 3×3 बास्केटबॉल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरीश शर्मा 3×3 ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप (पुरुष व महिला) के दूसरे संस्करण के लिए देशभर से 127 से अधिक टीमों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 और 28 दिसंबर को केडी जाधव इंडोर हॉल, इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति की अध्यक्ष रूपम हरीश शर्मा ने बताया कि पंजीकृत टीमों में से 87 टीमों का अंतिम चयन किया जाएगा, जिनमें 63 पुरुष और 24 महिला टीमें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कुछ अर्जुन पुरस्कार विजेता और एक पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। यह प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बास्केटबॉल खिलाड़ी और खेल प्रशासक रहे स्वर्गीय हरीश शर्मा की स्मृति में आयोजित की जा रही है।

महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में चमक बिखेरने को तैयार रांची रॉयल्स, अनुभव और घरेलू जोश बनेगा ताकत

नई दिल्ली। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सत्र से पहले रांची रॉयल्स अपनी घरेलू धरती पर नए इरादों और संतुलित टीम संयोजन के साथ उतरने को तैयार है। घरेलू खिलाड़ियों के मजबूत समर्थन और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के मेल के साथ रॉयल्स इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में नजर आ रही है। टीम ने नीलामी से पहले नेहा गोयल, इशिका चौधरी और रुतुजा दादासो पिसाल को बरकरार रखते हुए अपनी कोर टीम को सुरक्षित रखा, वहीं सितंबर में हुई मिनी-नीलामी में कुछ अहम खिलाड़ियों को जोड़कर स्क्वाड को और मजबूत किया। गोलकीपिंग विभाग में भारतीय टीम की अनुभवी गोलकीपर बिचू देवी खारीबाम की एंट्री से टीम की रक्षा पंक्ति को मजबूती मिली है, जबकि माधुरी किंडो भी भरोसेमंद विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। रक्षा पंक्ति में निक्की प्रधान और इशिका चौधरी जैसी अनुभवी भारतीय खिलाड़ी टीम की रीढ़ होंगी। उनके साथ अर्जेंटीना की लुसीना वॉन डेर हेडे और मारिया सोफिया डार्ने एलियास जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे संतुलन प्रदान करेंगे। नीदरलैंड्स की सबीने प्लोनिसन और जूनियर विश्व कप में प्रभावित करने वाली लालथांतलुआंगी भी टीम को गहराई देंगी।

खेल पेशेवरों के लिए नई इंटर्नशिप नीति लॉन्च

एजेंसी

नई दिल्ली। नई नीति के तहत, युवा मामले और खेल मंत्रालय और इसके प्रमुख संस्थानों में सालाना 452 इंटर्नशिप की पेशकश की जाएगी। इनमें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) शामिल हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संरचित, बड़े पैमाने का मंच बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक इंटर्नशिप नीति लॉन्च की। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, 'भारत के खेल ईकोसिस्टम में बदलाव के लिए कुशल पेशेवरों और युवा प्रतिभाओं की ओर से समर्थित मजबूत संस्थागत समर्थन की जरूरत है। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के जरिए हम युवाओं के लिए खेल शासन और प्रशासन के द्वार खोल रहे हैं, जिससे वे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें और खेलों के जरिए राष्ट्र निर्माण में दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकें। '

डॉ. मांडविया के अनुसार, यह कार्यक्रम पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लोगों की बढ़ती जरूरत को पूरा

करता है। भारत अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, गवर्नेंस सुधारों को मजबूत कर रहा है और खेल की दुनिया में अपनी पहचान बढ़ा रहा है। यह पहल युवाओं को भारत की खेल यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल नीति और खेलो भारत नीति 2025 के उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें युवा सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण और खेल प्रशासन के व्यवसायीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति भारत के उस दूरगामी दृष्टिकोण का समर्थन करती है जिसमें एक ऐसा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो भविष्य के लिए तैयार हो, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी कर सके।

इंटर्नशिप 20 से ज्यादा फंक्शनल डोमेन में होंगी, जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट ऑपरेशंस, मीडिया और कम्युनिकेशन, कानूनी मामले, आईटी सिस्टम, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी-डोपिंग शामिल हैं। स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च, लेबोरेटरी टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस और एथलीटों को साइंटिफिक सपोर्ट पर खास ध्यान दिया जाएगा।

नाडा में शामिल इंटर्न्स एंटी-डोपिंग जागरूकता, कानूनी अनुपालन, केस मैनेजमेंट और पॉलिसी सपोर्ट में मदद करेंगे, जबकि एनडीटीएल में काम करने वाले इंटर्न्स को सैंपल एनालिसिस और रिसर्च सहित एडवांस्ड लेबोरेटरी-आधारित एंटी-डोपिंग प्रक्रियाओं का अनुभव मिलेगा। प्रतिवर्ष दो रिक्रूटमेंट साइकिल जनवरी और जुलाई में होंगी।

महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास

एजेंसी

विशाखापत्तनम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 22 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शेफाली ने अपने करियर में अब तक कुल 92 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 26.73 की औसत के साथ 2,299 रन बनाए। इस दौरान शेफाली ने 12 अर्धशतक लगाए। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र से पहले 10 अर्धशतक लगाए थे। आयरलैंड की गैबी लुईस 10 अर्धशतकों के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जबकि भारत की जेमिमा रोड्रिग्स (7) लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के विरुद्ध दूसरे टी20 मैच में शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों में

अर्धशतक पूरा किया। यह श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

नीरज चोपड़ा ने पत्नी के साथ प्रधानमंत्री से की मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व प्रसिद्ध भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। यह भेंट प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई, जिसमें खेल से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से आज 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। खेल सहित कई विषयों पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। ' प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज चोपड़ा ने भी 'एक्स' पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का समय

देने के लिए धन्यवाद। खेलों के प्रति आपका दृष्टिकोण और समर्थन हम सभी भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक रहा है। 'उल्लेखनीय है कि नीरज चोपड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है और उनकी उपलब्धियों ने देश में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीबीएलः स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से हराकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर स्टार्स

एजेंसी

एडिलेड । मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड ओवल में खेले गए बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 के 10वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ स्टार्स ने प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर कब्जा जमा लिया है। मेलबर्न स्टार्स ने इस सीजन के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर 4 प्वाइंट्स हासिल किए हैं, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स पहला मैच जीतने के बाद अगला मुकाबला हार गई। यह टीम छठे स्थान पर लुढ़क गई है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम ने 7 के स्कोर पर क्रिस लिन (4) और जेसन सांघा (0) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने लियाम स्कॉट के साथ तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को परेशानी से निकाला। लियाम 19 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

मैथ्यू शॉर्ट ने एलेक्स रॉस के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन जोड़ते हुए टीम को 110 के स्कोर

तक पहुंचाया। शॉर्ट 42 गेंदों में 4 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रॉस ने 22 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की तरफ से टॉम करन और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि पीटर सिडल और मार्कस स्टोइनिस ने 1-1 विकेट निकाला। इसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स ने 18.1 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। जो क्लार्क ने सैम हार्पर के साथ 7 ओवरों में 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। क्लार्क 19 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद सैम हार्पर ने 36 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 55 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इनके अलावा, कैंपबेल केलवे ने 28 रन बनाए, जबकि कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने नाबाद 32 रन बनाकर टीम को आसान जीत दिलाने में योगदान दिया। विपक्षी टीम के लिए हसन अली ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि जेमी ओवरटन और लॉयड पोप ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

आईसीसी रैंकिंगः दीप्ति शर्मा बनी नंबर वन टी20 गेंदबाज, मंधाना को एक स्थान का नुकसान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा टी20 फॉर्मेट की नई नंबर वन गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ते हुए नंबर वन का ताज हासिल किया है। शीर्ष दस में दीप्ति एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की सादिया इकबाल हैं। दोनों को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन और पांचवें स्थान पर लॉरेन बेल हैं। छठे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की एन मल्बा, सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉरहेम, आठवें पर इंग्लैंड की चॉर्ली डेन, नौवें स्थान पर वेस्टइंडीज की एफी फ्लेचर और दसवें स्थान पर पाकिस्तान की नशरा संधु हैं। महिलाओं की नई वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान

लौरा वोल्वार्ड्ट एक बार फिर से स्मृति मंधाना को पछाड़ते हुए नंबर वन स्थान पर काबिज हो गई हैं। उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। मंधाना दूसरे स्थान पर हैं, उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर, चौथे स्थान पर नट सेवियर ब्रंट, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलीसा हिली, सातवें स्थान पर न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, आठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एल्सी पेरी, नौवें स्थान पर हेली मैथ्यूज और दसवें स्थान पर भारत की जेमिमा रोड्रिग्ज हैं। महिलाओं की वनडे रैंकिंग में सिर्फ मंधाना और वोल्वॉर्ड्ट की रैंकिंग में ही बदलाव दिखा है।

महिलाओं की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज दूसरे, भारत की स्मृति मंधाना तीसरे, ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ चौथे, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट पांचवें, श्रीलंका की चमारी अट्टपट्टू छठे, दक्षिण अफ्रीका की तंजिम ब्रिट्स सातवें, न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स आठवें और भारत की जेमिमा रोड्रिग्स नौवें स्थान पर हैं। रोड्रिग्स को पांच स्थान का फायदा हुआ है। शेफाली वर्मा दसवें स्थान पर हैं। उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है।

विजय हजारे ट्रॉफीः चिन्नास्वामी स्टेडियम में बिना दर्शकों के होगा दिल्ली और आंध्र प्रदेश का मैच

एजेंसी

बेंगलुरु । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट की वनडे फॉर्मेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी के अंतर्गत दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में मैच आयोजित होना है। कर्नाटक पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की चिंताओं का हवाला देते हुए दर्शकों की मौजूदगी में मैच के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। यह फैसला बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकारियों और अग्निशमन विभाग की जांच के बाद लिया गया है। जांच में वेन्यू में गंभीर कमियां पाई गयी हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'गृह विभाग के निर्देश पर कमेटी सोमवार को स्टेडियम गई थी। फायर, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेसकॉम), ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और पुलिस समेत अलग-अलग विभाग के अधिकारियों ने स्टेडियम का इंस्पेक्शन किया था। अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच के लिए इजाजत नहीं दी गई है। कमेटी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी दी है। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने पहले ही जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में 17-पॉइंट की एडवाइजरी जारी कर दी थी। कमिटी ने एडवाइजरी की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ' पुलिस के मुताबिक, स्टेडियम के गेट बहुत ज्यादा भीड़ को संभालने के लिए बहुत छोटे थे। विराट कोहली के आने की स्थिति में भारी भीड़ आने की संभावना है। इस विषय पर कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से मुलाकात कर छूट देने की मांग की, लेकिन अधिकारी नहीं माने।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पर्सनैलिटी राइट्स केस' में सुनील गावस्कर से जुड़े कंटेंट हटाने का आदेश दिया

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक अंतरिम रोक लगाई और सोशल मीडिया माध्यमों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम और तस्वीर के इस्तेमाल वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल-जज बेंच ने मेटा और एक्स कॉर्प समेत प्लेटफॉर्म्स को यह आदेश दिया कि गावस्कर के बारे में गलत बयान वाले यूआरएल 72 घंटे के अंदर हटा दिए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर उपभोक्ता तय समय के अंदर उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने में असफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट तक एक्सेस को बंद करना होगा। जस्टिस अरोड़ा ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को गावस्कर के

नाम पर बिना अनुमति के बेचे जा रहे उत्पादों की सूची हटाने का भी निर्देश दिया, और कहा कि अगर विक्रेता 72 घंटे के अंदर उल्लंघन करने वाले उत्पाद हटाने में फेल हो जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म्स उन्हें डीलिस्ट कर देंगे। यह अंतरिम राहत गावस्कर को उस केस में मिली जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बिना उनकी इजाजत के उनसे जुड़ी चीजों के खिलाफ इस्तेमाल के खिलाफ अपनी पर्सनैलिटी के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। पूर्व क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया पेज उनके नाम से मनगढ़ंत बातें बता रहे थे, जबकि कई ऑनलाइन विक्रेता उनसे गलत तरीके से जुड़े नकली ऑटोग्राफ वाले आइटम और दूसरा सामान बेच रहे थे। पहले की सुनवाई में, जस्टिस अरोड़ा ने गावस्कर से गूगल, मेटा और एक्स को गलत यूआरएल देने को कहा था, साथ ही इंटरमीडियरी को एक हफ्ते के अंदर सूचना तकनीक नियम, 2021 के तहत उनके अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।गावस्कर का मामला उन हाई-प्रोफाइल पर्सनैलिटी की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

लॉन टेनिस में हरियाणा की मधु ने बढ़ाया प्रदेश का मान

एजेंसी

चंडीगढ़। गुजरात के गांधी नगर में हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 में हरियाणा की मधु मान ने एक बार फिर दमखम दिखाया। हरियाणा में तकनीकी शिक्षा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर (प्रशासन) मधु मान इन खेलों में दो सिल्वर मेडल हासिल करने वाली उत्तर भारत की पहली महिला अधिकारी व खिलाड़ी हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड सहित किसी राज्य की महिला खिलाड़ी इस बार अवार्ड नहीं जीत पाई। मधु मान ने इन खेलों में अवार्ड जीतकर एक और रिकार्ड अपने नाम किया है। वे देश की पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं, जो पिछले सात वर्षों से लगातार इन राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रही हैं और अवार्ड जीत रही हैं। इससे पहले वे चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर रही और यूटी की ओर से खेलों में भाग लेती रहीं। पहली बार वे हरियाणा से खेली हैं। इन खेलों का आयोजन सेंट्रल सिविल सर्विसिज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड

नई दिल्ली द्वारा करवाया गया।मिक्स वैटर्न 45 प्लस डबल में मधु मान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं वुमन डबल्स में भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। मिक्स वैटर्न 45 प्लस डबल में मधु मान का मुकाबला गुजरात के साथ हुआ। आईआरएस ऑफिसर धर्मेंद्र शर्मा और वंदना सागर के साथ हुए मुकाबले में वे दूसरे स्थान पर रहीं। सेमीफाइनल में वे आंध्र प्रदेश की अंजनी साहू को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थीं।

मधु मान 2018 से लगातार इन खेलों में भाग ले रही हैं और पदक भी जीत रही हैं। 2018-19 में पुणे में हुए खेलों में उन्होंने दो गोल्ड और एक सिल्वर अपने नाम किया था। कोविड-19 के दौरान इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। 2021 में जयपुर में हुए खेलों में मधु मान ने दो गोल्ड मेडल झटके। इसी तरह से चंडीगढ़ में हुए आयोजन में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल, 2022 में पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुए मुकाबले में एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल हासिल किया तथा 2024-25 में उदयपुर में हुए खेलों में दो गोल्ड मेडिल हासिल किए।

यूपी की अंडर-14 बालिका हैंडबॉल टीम में एक विद्यालय की सात छात्राओं चयन

एजेंसी

वाराणसी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए यूपी की टीम का चयन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की अंडर-14 बालिका हैंडबॉल टीम के लिए जिले के शिवपुर परमानंदपुर के विकास इंटर कॉलेज की सात छात्राओं काचयन हुआ औ। उक्त जानकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. एके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी।

प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिनमें से अकेले विकास इंटर कॉलेज की सात छात्राओं का चयन होना विद्यालय के लिए गर्व की बात है। डॉ. सिंह ने बताया कि विद्यालय की छात्रा अनैशा सिंह, वंशिका प्रजापति, सेजल सिंह, सोनाली पाल, आयुषी पाल, रितिका प्रजापति और महिमा चौहान को उत्तर प्रदेश की अंडर-14 बालिका हैंडबॉल टीम में स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के 74 जिलों से केवल पांच अन्य खिलाड़ियों को टीम में स्थान मिला है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

ओलंपिक 2036 में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे : नायब सैनी

एजेंसी

चंडीगढ़। ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस ओलम्पिक में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे और इस प्रदेश के खिलाड़ी धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान की धरा के रूप में विश्व में बनी पहचान को ओर आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल व पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने सांसद खेल महोत्सव 2025 के विजेताओं को नकद राशि व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने शूटर गुरजोत सिंह और पैरा एथलैटिक के खिलाड़ी दिलबाग सिंह हिसार को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री इस सफल आयोजन के लिए सांसद नवीन जिंदल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि इस सांसद खेल महोत्सव-2025 में सबसे ज्यादा एक लाख 10 हजार खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखायी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में

साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया जाता है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हरियाणा में 11 साल पहले खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वे ओलंपिक हों, एशियाई हों या राष्ट्रमंडल खेल हों। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। यह सांसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढाने का माध्यम है। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। हमने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास-वन से क्लास-फोर तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देते हैं। हमने अब तक 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख के नकद पुरस्कार दिए हैं। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

केएसएच इंटरनेशनल का शेयर करीब चार फीसदी की गिरावट के साथ सूचीबद्ध

एजेंसी

नई दिल्ली। 'मैग्नेट वाइंडिंग' वायर बनाने वाली कंपनी केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर अपने निर्गम मूल्य 384 रुपये के मुकाबले करीब 4 फीसदी की गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) 2,437.85 करोड़ रुपये रहा। केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सेंचज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सेंचज (एनएसई) दोनों पर शेयर 370 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 3.64 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई पर यह 7.55 फीसदी की गिरावट के साथ 355 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर कंपनी का शेयर 7.81 फीसदी टूटकर 354 रुपये पर आ गया। केएसएच इंटरनेशनल ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 365-384 रुपये प्रति शेयर तय किया था। महाराष्ट्र के पुणे स्थित इस कंपनी का आईपीओ 420 करोड़ रुपये के नए निर्गम और 290 करोड़ रुपये के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था।

बैंकिंग तंत्र में नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई खरीदेगा 2,00,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर-जनवरी में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और डॉलर/रुपया स्वैप के जरिये बैंकिंग तंत्र में लगभग 2,89,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सुनिश्चित करेगा।केंद्रीय बैंक ने बताया कि वह चार बराबर किस्तों में 2,00,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। इसके अलावा वह डॉलर/रुपया खरीद/बिक्री स्वैप के तहत 1,000 करोड़ डॉलर (लगभग 89,000 करोड़ रुपये) के अनुबंध करेगा। रिजर्व बैंक के इन उपायों से बैंकिंग तंत्र में लगभग 2,89,000 करोड़ रुपये की नकदी आयेगी। इस कदम से बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी और उनकी पूंजी लागत कम होगी।यह आरबीआई द्वारा इसी महीने पहले की गयी एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति की खरीद और 500 करोड़ डॉलर के स्वैप ऑक्शन के अतिरिक्त है। केंद्रीय बैंक ने 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को 50-50 हजार रुपये की दो किस्तों में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की थी। वहीं, 16 दिसंबर को उसने स्वैप ऑक्शन के तहत 500 करोड़ डॉलर खरीदे थे। आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि तरलता और वित्तीय स्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद 50-50 हजार करोड़ रुपये की चार किस्तों में 29 दिसंबर, 05 जनवरी, 12 जनवरी और 22 जनवरी को की जायेगी।

अडानी पोर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के एनक्यूएक्सटी टर्मिनल का अधिग्रहण पूरा किया

अहमदाबाद।बंदरगाह कारोबार की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड प्रांत में ऐबट प्वाइंट पोर्ट की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस सौदे में किसी प्रकार की नकदी का लेनदेन नहीं हुआ है। ऐबट प्वाइंट पोर्ट की प्रवर्तक कंपनी करमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर को बदले में प्राथमिकता के आधार पर इक्विटी शेयर जारी किये गये हैं जिनका मूल्य मंगलवार के बंद भाव के अनुसार 21,483 करोड़ रुपये से अधिक है। अडानी पोर्ट्स ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस सौदे के लिए बहुलांश और अल्पांश शेयरधारकों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और ऑस्ट्रेलिया विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड समेत सभी नियामकों की मंजूरियां भी मिल चुकी हैं। ऐवट प्वाइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में गहरे पानी के प्राकृतिक टर्मिनल एनक्यूएक्सटी का संचालन करती है। इस निर्यात टर्मिनल की सालाना क्षमता पांच करोड़ टन है और प्रांतीय सरकार ने इसे लंबी अवधि की लीज पर आवंटित किया है। लीज की अवधि साल 2110 में समाप्त होगी। अडानी पोर्ट्स ने करमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर को दो रुपये अंकित मूल्य के 14,38,20,153 शेयर आवंटित किए हैं। आज बाजार बंद होते समय कंपनी का शेयर 1,493.75 रुपये पर बंद हुआ था। इस हिसाब से इस सौदे का मूल्य 21,483 करोड़ रुपये से अधिक होता है।

आयकर रिटर्न में सुधार का एक और मौका

मुंबई। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न में गड़बड़ी पाये जाने के बावजूद कार्रवाई के बदले उसमें स्वयं सुधार का एक मौका देते हुए ऐसे करदाताओं से 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न भरने की अपील की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जिन करदाताओं के रिटर्न में रिफंड के गलत दावे किये गये हैं या दावों में खामियां पायी गयी हैं उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिये सूचित किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में सीधे कार्रवाई करने की बजाय चिह्नित करदाताओं को भी संशोधित रिटर्न भरने का एक और मौका दिया जा रहा है। वे भी 31 दिसंबर तक खामियों को ठीक करते हुए संशोधित रिटर्न भर सकते हैं।उसने बताया कि चिह्नित मामलों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों या अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिखाकर रिफंड के दावे किये गये हैं। इनमें कई मामलों में दान स्वीकार करने वाले का पैन नबंर गलत या अवैध पाया गया है। विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में 21 लाख से अधिक करदाताओं ने पिछले चार आंकलन वर्ष के अपने रिटर्न को अपडेट करते हुए 2,500 रुपये का अतिरिक्त कर जमा कराया है।

एफटीए से भारतीय पेशेवरों के लिए विदेशों में अवसर खुलेंगे : राजेश अग्रवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से लेखाकार, चिकित्सकों तथा 'आर्किटेक्ट' जैसे पेशेवरों के लिए विदेशों में अवसर खुलेंगे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने प्रोफेशनल सेवाओं पर नई दिल्ली में 23 दिसंबर को वाणिज्य भवन में आयोजित एक चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए यह बात कही। राजेश अग्रवाल ने 'वैश्विक क्षितिज का विस्तारः भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर' विषय पर आयोजित विचार-विमर्श सत्र को संबोधित करते कहा कि एफटीए के तहत प्रोफेशनल सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल मार्केट खोलेंगी। अग्रवाल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सेवाओं का व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामान के निर्यात की तुलना में सेवाएं घरेलू वैल्यू एडिशन में मज़बूत योगदान देती हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश पेशेवर सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने की अपार क्षमता रखता है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना एवं पेशेवरों को बदलते वैश्विक बाजार की जरूरतों तथा प्रौद्योगिकी विकास के अनुरूप उन्नत कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) जैसे पेशेवर निकायों को ज्ञान साझा करने एवं बेहतर सहयोग के लिए मंच प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने और उनमें हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अग्रवाल ने 'भारतीय पेशेवर सेवाओं की खातिर वैश्विक बाजारों को खोलने के लिए हितधारकों के बेहतर समन्वय, घरेलू परिवेश में सुधार और विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत पेशेवर सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के महत्व पर जोर दिया।'' वाणिज्?य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 'वैश्विक क्षितिज का विस्तारः भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर' विषय पर आयोजित विचार-विमर्श सत्रों के दौरान चार मुख्य मुद्दों, वैश्विक स्तर पर पेशेवर तैयार करना, पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) तथा समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिवहन को मजबूत करना, विदेशों में पेशेवरों के नेटवर्क का विकास, गठन एवं विस्तार और पेशेवर सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत को विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ घोषित समझौता भी शामिल है, जिसके तहत उसके पेशेवरों के लिए आसान नियम और वीजा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस समझौते के तहत योग प्रशिक्षकों, रसोइयों, आयुष पेशेवरों, आईटी पेशेवरों, शिक्षा शिक्षकों, नर्स, देखभालकर्ताओं जैसे लगभग 5,000 भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए पेशेवर वीजा मिलेगा।

गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी का आईपीओ दूसरे दिन 2.67 गुना हुआ सब्सक्राइब

एजेंसी

नई दिल्ली। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बोली लगाने के दूसरे दिन 2.67 गुना सब्सक्राइब हुआ। इश्यू को ऑफर किए गए 1,32,26,880 इक्विटी शेयरों के मुकाबले 3,53,72,544 इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसके खुदरा भाग और गैर-संस्थागत भाग क्रमशः 10.45 और 2.95 गुना सब्सक्राइब हुए। वहीं, योग्य संस्थागत निवेशक 0.34 गुना सब्सक्राइब हुए। यह इश्यू सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 24 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ से 250.80 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पूरी तरह से 2.20 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू है, जिसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इस आईपीओ का आवंटन 26 दिसंबर को होने की उम्मीद है, जबकि सफल आवेदकों को 29 दिसंबर को शेयर मिलने की संभावना है। इसके शेयर बीएसई और एनएसई पर 30 दिसंबर को सूचीबद्ध होने वाले है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी मध्य गुजरात में स्थित क्षेत्रीय हेल्थकेयर कंपनियों में से एक है, जो मध्यम आकार के मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों की चेन संचालित करती है।

Gujarat Superspeciality Hospital

भारत और न्यूजीलैंड ने एफटीए के तहत वित्तीय सेवाओं पर एनेक्स को अंतिम रूप दिया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत-न्यूजीलैंड ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के वित्तीय सेवाएं अनुबंध पर बातचीत पूरी कर ली, जो द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। दोनों देशों के बीच 10 दिसंबर को हुई वार्ता के आखिरी दौर के बाद 22 दिसंबर को बातचीत औपचारिक रूप से पूरी हुई। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि वित्तीय सेवाएं अनुबंध पर बातचीत मई में शुरू हुई और यह 18 आर्टिकल्स वाले एक बड़े ढांचा में बदल गई, जिसमें भारत के पिछले मुक्त व्यापार समझौता के अनुभव का इस्तेमाल किया गया। मंत्रालय के मुताबिक यह एक दूरदर्शी और संतुलित समझौता है, जो डिजिटल भुगतान, फिनटेक, डेटा अंतरण और बैक-ऑफिस सेवाओं पर नवोन्मेषी प्रावधानों के साथ वित्तीय सेवाओं में द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करेगा। इससे भारतीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए यूपीआई और एनपीसीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में भारत की प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए बाजार के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रालय के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ एफटीए घरेलू संस्थानों के साथ समान व्यवहार करेगा। यह भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाजार पहुंच को सुविधा प्रदान करेगा। यह भारत और न्यूजीलैंड की वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है। इस संबंध के महत्व को समझते हुए दोनों देशों ने मिलकर एक दूरदर्शी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को विकसित करने के लिए काम किया है, जिससे उनके संबंधित वित्तीय सेवा क्षेत्रों के लिए बेहतर अवसर खुलेंगे। यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय सहयोग को गति देने, बाजार पहुंच को सुगम बनाने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणालियों के गहन एकीकरण के लिए आवश्यक संस्थागत और नियामकीय ढांचा प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा अनुबंध की प्रमुख उपलब्धियों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और वास्तविक-समय लेनदेन अवसंरचना, वित्तीय प्रौद्योगिकी और नियामकीय नवोन्मेषण, वित्तीय सूचना का हस्तांतरण और संरक्षण, क्रेडिट रेटिंग और गैर-भेदभाव, बैंक-ऑफिस और सहायक कार्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेश सीमा और बैंक शाखाओं में वृद्धि शामिल हैं। कुल मिलाकर, भारत-न्यूजीलैंड वित्तीय सेवा अनुबंध पर वार्ता के सफल समापन से दोनों सरकारों की आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय सेवा परिदृश्य में पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

कावासाकी निंजा 300 पर बंपर ऑफर, कैश डिस्काउंट के बाद कीमतों में आई गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। साल के अंत में कावासाकी का बड़ा ऐलान साल के आखिर में बाइक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कावासाकी इंडिया ने अपनी मोटरसाइकिल रेंज पर खास छूट का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कंपनी की लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक कावासाकी निंजा 300 को भी शामिल किया गया है। कावासाकी इस बाइक पर सीधे 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो गई है। यह ऑफर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं।

ऑफर की शर्तें और वैधता

कंपनी की ओर से दी जा रही यह छूट केवल MY2024 मॉडल पर लागू है। कावासाकी ने साफ किया है कि यह ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक या फिर स्टॉक खत्म होने

तक ही मान्य रहेगा। ऐसे में जो ग्राहक इस बाइक को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अहम हो सकता है। कावासाकी इस तरह के ऑफर्स के जरिए अपने मौजूदा स्टॉक को तेजी से क्लियर करने की रणनीति पर काम कर रही है। कैश डिस्काउंट के बाद कावासाकी निंजा 300 की कीमत में साफ बदलाव देखने को मिलता है। इस बाइक की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 3.17 लाख रुपये है। 25,000 रुपये की छूट लागू होने के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत घटकर 2.92 लाख रुपये रह जाती है। इस कीमत पर निंजा 300 उन राइडर्स के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाती है, जो ट्विन-सिलेंडर इंजन और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के साथ एक स्पोर्ट्स बाइक की तलाश में हैं। भारतीय बाजार में कावासाकी निंजा 300 को लॉन्च हुए एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है। लंबे समय से बिक्री में होने के बावजूद इसके डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, जिसके चलते यह बाइक अब थोड़ी पुरानी जरूर लगती है। इसके बावजूद इसके हार्डवेयर को आज भी मजबूत माना जाता है। इसमें फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस भी मौजूद है।

रेज पावर इंफ्रा के रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म में 1,350 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगा एपी मोलर कैपिटल

नई दिल्ली। रेज पावर इंफ्रा लिमिटेड ने कहा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एपी मोलर कैपिटल का इमर्जिंग मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड II (ईएमआईएफ II होल्डिंग) कंपनी की ओर से बनाए जा रहे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 1,350 करोड़ रुपये तक निवेश करेगा। यह निवेश प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी के जरिए होगा। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि इस निवेश से कम से कम 5,200 करोड़ रुपये का कुल प्रोजेक्ट खर्च आएगा। इससे हमारे काम को बड़ा स्केल मिलेगा, लंबे समय तक कमाई की स्पष्ट तस्वीर बनेगी और आगे कई नए सहयोग के मौके खुलेंगे। यह निवेश एपी मोलर कैपिटल फंड्स का भारत में पहला निवेश है। इससे साफ होता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्लोबल हब बनता जा रहा है और देश की लंबी अवधि की आर्थिक बुनियाद पर भरोसा बढ़ रहा है। रेज पावर इंफ्रा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) केतन मेहता ने कहा कि एपी मोलर कैपिटल के साथ यह साझेदारी रेज पावर इंफ्रा के लिए बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने काह कि यह हमारी लंबी सोच को मजबूत करती है कि बड़े स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। उनका निवेश हमारी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की ताकत को साबित करता है और भारत भर में बड़े सोलर एसेट्स तेजी से देने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। एपी मोलर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ किम फेजफर ने कहा, 'हमें खुशी है कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में यह पहला बड़ा कदम रख रहे हैं। भारत का एनर्जी ट्रांजिशन दुनिया में सबसे आकर्षक लंबी अवधि का इंफ्रास्ट्रक्चर मौका है। यहां मजबूत पॉलिसी सपोर्ट और मार्केट की बुनियाद से अभूतपूर्व ग्रोथ हो रही है। एपी मोलर ग्रुप के भारत में दशकों के अनुभव और एपी मोलर कैपिटल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस विकसित करने के तजुर्बे के साथ हम बड़े स्केल पर काम करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इससे भारत के तेजी से परिपक्व हो रहे रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ' रेज पावर इंफ्रा लिमिटेड ने बताया कि एपी मोलर कैपिटल, एपी मोलर समूह की 120 से ज्?यादा सालों की इंडस्ट्रियल विरासत और हैंड्स-ऑन वैल्यू क्रिएशन की संस्कृति का लाभ उठाते हुए, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में निवेश करने और उन्हें बढ़ाने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, जिसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड-पावर बिजनेस, ग्रिड सॉल्यूशन और एनर्जी-एफिशिएंसी एसेट्स शामिल हैं।

यामाहा मोटर इंडिया समूह के नये चेयरमैन हाजिमे ओटा एक जनवरी को संभालेंगे कार्यभार

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने हाजिमे ओटा को यामाहा मोटर इंडिया समूह का नया चेयरमैन नियुक्त करने का ऐलान किया है। वह एक जनवरी, 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे।कंपनी के मुताबिक भारत में नियुक्ति से पहले ओटा यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड में कार्यकारी अधिकारी तथा जापान स्थित कंपनी के वैश्विक मुख्यालय में कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी सेंटर के मुख्य महाप्रबंधक (सीएसओ) के तौर पर सेवा दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट रणनीति, सतत विकास पहल और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व किया।हाजिमे ओटा ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि भारत में यामाहा का नेतृत्व करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ओटा ने आगे कहा कि मेरा ध्यान ऐसे उत्पाद पेश कर ब्रांड को मजबूत करने पर रहेगा, जो यामाहा की वैश्विक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों के साथ सहज रूप से जोड़ते हों। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सबसे गतिशील और विविधतापूर्ण दोपहिया वाहन बाजारों में से एक है।

सरकार खुदरा महंगाई की गणना में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन स्त्रोतों को करेगी शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की विश्वसनीयता, सटीकता और गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से खुदरा महंगाई की गणना में ऑनलाइन स्त्रोतों के साथ-साथ ई-कॉमर्स मंच को भी शामिल करेगी। सीपीआई की नई श्रृंखला के आंकड़े 12 फरवरी को जारी किए जाने की संभावना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीपीआई, जीडीपी और आईआईपी के आधार में वर्ष संशोधन पर दूसरी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी और मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव, एन. के. संतोषी, महानिदेशक (केंद्रीय

सांख्यिकी), उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और नीति निर्माण निकायों के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नए आंकड़ा स्त्रोतों को शामिल करने के संबंध में कहा कि वर्तमान श्रृंखला में भौतिक दुकानों से एकत्र किए जा रहे आंकड़ों के अतिरिक्त 25 लाख से अधिक आबादी वाले 12 चयनित शहरों में ई-कॉमर्स मंच से भी कीमत आंकड़े प्राप्त की जाएंगी। रेल किराया के लिए रेलवे, ईंधन की कीमतों के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और डाक शुल्क के लिए डाक विभाग के साथ समन्वय में प्रशासनिक आंकड़े प्राप्त करने के भी प्रयास किए जाएंगे। एमओएसपीआई ने बताया कि हवाई किराये, दूरसंचार सेवाओं और ओटीटी (ओवर द टॉप) मंच के लिए, वेब-आधारित तरीकों का उपयोग करके ऑनलाइन स्त्रोतों से मूल्य आंकड़े संकलित करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय के अनुसार इन वैकल्पिक और डिजिटल डेटा स्त्रोतों को अपनाने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रतिनिधित्व क्षमता, विश्वसनीयता, सटीकता और समग्र गुणवत्ता में काफी सुधार होने की उम्मीद है। जीडीपी आधार वर्ष संशोधन से नए आंकड़ों के स्त्रोतों को शामिल करने और संकलन प्रक्रिया कार्यप्रणालीगत सुधारों, मानकों और वर्गीकरणों के अनुरूप बनाने में भी सुविधा होगी। सीपीआई, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना के लिए आधार वर्षों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय लेखा संबंधी आंकड़े 27 फरवरी को जारी करेगी, जबकि 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए आईआईपी की नई श्रृंखला के आंकड़े 28 मई को जारी होंगे।

शेयर बाजार कारोबार में स्थिर रुख के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 43 टूटा

एजेंसी

नई दिल्ली। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लग गया। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बाजार के दोनों मानक सूचकांक लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 42 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी मामूली लाभ में रहा।बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 42.63 अंक यानी 0.050 फीसदी की गिरावट के साथ 85,524.84 के स्?तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 85,704.93 अंक के उच्चतम स्तर तक गया और उसके बाद 85,342.99 अंक के न्यूनतम स्तर तक आया। वहीं, नेशनल स्?टॉक एक्?सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 4.75 अंक यानी 0.018 फीसदी बढ़कर 26,177.15 के स्तर पर बंद हुए।

सूचना प्रौद्योगिकी और औषधि बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली से शेयर बाजार नीचे आया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 शेयर में गिरावट दिखी। इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एयरटेल में 1.5 फीसदी तक गिरावट रही है। आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टीएमपीवी 1 फीसदी बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स के अन्?य शेयरों में भारती एयरटेल, अडाणी पोर्ट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इटर्नल, एक्सिस बैंक और मारुति प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। लाभ में रहने वाले शेयरों में आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। इसके साथ ही निफ्टी के 50 में से 26 शेयर गिरकर बंद हुए। एनएसई के आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट रही, जबकि एफएमसीजी, मीडिया और मेटल ऊपर बंद हुए। इसके अलावा एशिया के अन्य शेयर बाजारों में शामिल दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में रहे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ है। यूरोप के बाजारों में दोपहर कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले सेंसेक्स 638.12 अंक यानी 0.75 फीसदी की उछाल के साथ 85,567.48 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 206 अंक यानी 0.79 फीसदी चढ़कर 26,172.40 के स्तर पर बंद हुआ था।

चावल, गेहूं, दालें मजबूत; खाद्य तेलों में घट-बढ़

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल के औसत भाव बढ़ गये। गेहूं और दालों में भी मजबूती देखी गयी। चीनी के दाम लगभग अपरिवर्तित रहे। वहीं, खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 14 रुपये बढ़कर 3,867 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं छह रुपये महंगा हुआ और 2,862 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। आटा पांच रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ।

दाल-दलहनों में तेजी रही। मूंग दाल की कीमत आठ रुपये और मसूर दाल की सात रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। चना दाल पांच रुपये और उड़द दाल तीन रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। तुअर दाल के भाव कमोबेश गत दिवस के स्तर पर ही रहे। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मार्च वायदा 51 रिंगिट चढ़कर 4036 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। वहीं, मार्च का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.18 प्रतिशत टूटकर 48.99 डॉलर के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में सोया तेल औसतन 42 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। वनस्पति की कीमत 31 रुपये और सरसों तेल की 21 रुपये बढ़ गयी। सूरजमुखी तेल और मूंगफली तेल 17-17 रुपये महंगे हुए। पाम ऑयल की कीमत 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। मीठे के बाजार में आज गुड़ की औसत कीमत लगभग स्थिर रही। चीनी में भी टिकाव रहा।

टाटा नेक्सन ईवी ने पार किया 1 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा, बनी देश की पहली इलेक्ट्रिक कार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार में नया कीर्तिमान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच टाटा मोटर्स ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। टाटा नेक्सन ईवी देश की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार बन गई है, जिसने 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि केवल एक मॉडल की सफलता नहीं, बल्कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तेजी से बढ़ते भरोसे का प्रतीक मानी जा रही है। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से ईवी सेगमेंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसमें नेक्सन ईवी की भूमिका सबसे अहम रही है।

लॉन्च के बाद से लगातार बढ़ता भरोसा

साल 2020 में भारतीय बाजार में कदम रखने वाली टाटा नेक्सन ईवी ने शुरुआत से ही ग्राहकों का ध्यान खींचा। दमदार परफॉर्मेंस, संतुलित रेंज और मजबूत ब्रांड वैल्यू ने इसे आम उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। समय के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सर्विस नेटवर्क के विस्तार ने भी इसकी बिक्री को मजबूती दी। आज नेक्सन ईवी को भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट की पहचान माना जाने लगा है।

पावरट्रेन और रेंज की पूरी जानकारी टाटा नेक्सन ईवी को दो अलग-

अलग बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है। इसमें पहला बैटरी पैक 30 kWh क्षमता का है, जो अच्छी पावर और संतुलित परफॉर्मेंस देता है। दूसरा विकल्प 40.5 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जिसे लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के अनुसार, छोटे बैटरी पैक के साथ यह ईवी एक बार चार्ज करने पर लगभग 325 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि बड़ा बैटरी पैक फुल चार्ज पर 465 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है।

फीचर्स में भी नहीं है कोई कमी

टाटा नेक्सन ईवी के केबिन को आधुनिक तकनीक और आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा, सिंगल पेन सनरूफ और प्रीमियम इंटीरियर फिनिश इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं।

सेफ्टी में भी कायम किया मानकः परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाटा नेक्सन ईवी को उच्च स्तर की सेफ्टी के साथ तैयार किया गया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत ह्ष्टक्क क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसी तकनीक दी गई है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

कीमत और बाजार में स्थिति

भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 17.49 लाख रुपये तक जाती है। इस कीमत पर मिलने वाली रेंज, फीचर्स और सेफ्टी इसे इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी नेक्सन ईवी भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगुवाई करती रहेगी।

जेन जी आंदोलन के बाद पहली बार सुशीला कार्की और ओली, देउवा, प्रचण्ड आमने-सामने

काठमांडू। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल की पहल पर मंगलवार को शीतल निवास में तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। इस बैठक में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेकपा के समन्वयक एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल तथा अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की शामिल हुए। इस संवाद को अंतरिम सरकार और प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक दूरी कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, बैठक में विशेष रूप से 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित संसदीय चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से संवाद को आगे बढ़ाने पर समझ बनी है। साथ ही, विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास बालुवाटार में जारी रखने पर भी सहमति हुई, हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति पौडेल के हवाले से कहा गया, 'देश एक गंभीर और संवेदनशील स्थिति में है। घोषित चुनावों को सफल बनाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। '

इजराइली हमले के बाद लेबनान का खंडन, कहा- हिज्बुल्लाह से सेना का संबंध नहीं

बेरूत। लेबनान नेइजराइल के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि दक्षिणी शहर सिडोन के पास हुए एक हवाई हमले में मारे गए लेबनानी सैनिक के हिज़्बुल्लाह से संबंध थे। इजराइल का दावा था कि उसने हिज्बुल्लाह के ढांचे को दोबारा खड़ा करने में जुटे तीन लड़ाकों को निशाना बनाया है। इजराइली सेना के अनुसार, मारे गए लोग उसके बलों पर हमलों की योजना बना रहे थे और इनमें से दो हिज्बुल्लाह की एयर डिफेंस यूनिट से जुड़े थे। इजराइल ने यह भी आरोप लगाया कि उनमें से एक व्यक्ति लेबनानी सेना की खुफिया इकाई में भी तैनात था। हालांकि, लेबनानी सेना ने बाद में पुष्टि की कि वारंट ऑफिसर अली अब्दुल्ला, जो सपोर्ट ब्रिगेड और एंटी-टैंक रेजिमेंट से जुड़े थे, सोमवार को सिडोन के पास एक वाहन पर हुए इजराइली हवाई हमले में मारे गए। लेबनान के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सेना के किसी भी कर्मी के राजनीतिक या सशस्त्र संगठनों से जुड़े होने के दावे पूरी तरह गलत हैं। रक्षा मंत्री मिशेल मेनासा ने ऐसे आरोपों को सेना की संस्था पर 'दुर्भावनापूर्ण हमला' करार दिया। हिज्बुल्लाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी स्थानीय मीडिया से बातचीत में लेबनानी सेना के किसी सदस्य से संगठन के संबंध होने से इनकार किया ।

इटली के राष्ट्रगान में मामूली बदलाव, अंतिम पंक्ति से हटाया गया 'सी!'

रोम। इटली ने अपने राष्ट्रीय गान ब्रदर्स ऑफ इटली में एक सूक्ष्म लेकिन प्रतीकात्मक बदलाव किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गान के अंत में प्रयुक्त जोरदार शब्द 'सी!' (हाँ!) को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया है। यह संशोधन हाल के हफ्तों में रक्षा स्टाफ द्वारा जारी निर्देशों के तहत लागू किया गया, जो मई में आधिकारिक गजट में प्रकाशित राष्ट्रपति के एक आदेश के अनुरूप है। उस आदेश में राष्ट्रगान के मूल संस्करण का उल्लेख किया गया था। इससे पहले प्रचलित रूप में गान की अंतिम पंक्ति इस तरह समाप्त होती थी– 'हम मरने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, इटली ने पुकारा है! सी! ' सरकार ने इस बदलाव का सार्वजनिक प्रचार नहीं किया। सबसे पहले 23 दिसंबर को इतालवी दैनिक इल फात्तो क्वोतिदियानो ने इसकी जानकारी दी, जिसे बाद में रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के कार्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की। राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि गीत की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। दरअसल, 1847 में कवि गोफ्रेडो मामेली द्वारा लिखे गए मूल बोलों में 'सी!' शब्द शामिल नहीं था। हालांकि, उसी वर्ष मिशेले नोवारो द्वारा रचित संगीत स्कोर में यह शब्द दर्ज मिलता है। ब्रदर्स ऑफ इटली–जो वर्तमान प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी का नाम भी है–इटली के एकीकरण से पहले लिखा गया था। सरकार की वेबसाइट पर राष्ट्रगान के मूल बोल और संगीत स्कोर दोनों के प्रतिरूप उपलब्ध हैं।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नेपाल में भी बवाल, विराटनगर में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन

विराटनगर (नेपाल)। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से किए गए हत्या के खिलाफ नेपाल में लगातार दो दिनों से आंदोलन जारी है। विश्व हिंदू परिषद और हिन्दू सम्राट सेना के बैनर तले नेपाली युवक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बावत नेपाल के सड़कों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा प्रहरियों की तैनाती कर दी गई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ सीमा पार विराटनगर में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन के साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शनकारियों ने आग लगाया और जमकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और बांग्लादेश सरकार पर हिंदू माइनॉरिटी के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। युवाओं ने इस अवसर पर नेपाल में मुस्लिम कमीशन को समाप्त करने की भी मांग उठाई।

बोंडी बीच हमले के 'फर्स्ट रिस्पोंडर्स' और नायकों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा नया पुरस्कार

एजेंसी

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि उन्होंने गवर्नर-जनरल से अनुरोध किया है कि बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों की जान बचाने वाले पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और अन्य नायकों के लिए एक विशेष सम्मान सूची बनाई जाए। ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम (एबीसी) के अनुसार, इन लोगों के नाम वर्ष 2026 में घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस सूची में पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ और वे आम नागरिक शामिल होंगे, जो आतंकी हमले के बाद बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अजनबियों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, वे सार्वजनिक सम्मान के हकदार हैं। यह सामूहिक गोलीबारी

की घटना 14 दिसंबर को हुई थी। यह हमला यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की संसद ने कड़े नए बंदूक कानून और विरोध प्रदर्शन से जुड़े नियम पास किए। यह बिल बुधवार तड़के करीब तीन बजे 18 के मुकाबले आठ वोटों से पास हुआ। इसमें आतंक से जुड़े संदिग्ध लोगों के लिए हथियार कानून और सख्त करने का प्रावधान भी शामिल है। अब यह कानून अंतिम मंजूरी के लिए निचले सदन में भेजा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा था कि बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले की वजह से इस साल क्रिसमस का समय दुख और शोक से भरा रहेगा। उन्होंने कैनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह हमला न सिर्फ यहूदी समुदाय पर हमला था, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों और समाज पर भी हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के कारण कई लोगों के लिए इस बार क्रिसमस का एहसास अलग होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने जिस साहस, दयालुता और करुणा का परिचय दिया, वह पूरे देश की सकारात्मक भावना को दिखाता है।

खालिदा जिया के बेटे तारिक पत्नी और बेटी के साथ 17 साल बाद लंदन से कल लौट रहे हैं बांग्लादेश

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के वनवास के बाद कल (25 दिसंबर) अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्वदेश लौट रहे हैं। तीनों लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेश के समयानुसार शाम 6:15 बजे बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से रवाना होंगे। उम्मीद है कि वे कल दोपहर के आसपास सिलहट होते हुए ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से पूर्वांचल के 300 फीट इलाके में एक स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े रहेंगे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद तारिक सड़क मार्ग से एवरकेयर अस्पताल जाएंगे। वो वहां अपनी बीमार मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलेंगे। खालिदा का वहां एक महीने से ज्यादा समय से इलाज चल रहा है। मां से मिलने के बाद वे गुलशन में फिरोजा जाएंगे। यहीं वह रुकेंगे। पार्टी वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी के अनुसार, उम्मीद है इस अवसर पर ढाका में लगभग 50 लाख लोग इकट्ठा होंगे। समर्थक एयरपोर्ट से 300 फीट इलाके तक सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। उधर, देश में अशांति के बीच तारिक की वापसी को सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।

कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की महिला की हत्या, भारतीय दूतावास ने जताया दुख; एक्शन में पुलिस

एजेंसी

टोरंटो । कनाडा के टोरंटो से एक 30 साल की भारतीय मूल की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या के बाद पुलिस ने पूरे कनाडा में एक संदिग्ध के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पीड़ित को जानता था। स्थानीय मीडिया ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। मृतक महिला की पहचान हिमांशी खुराना के तौर पर हुई है। महिला के अपराधी को ढूंढ़ने के लिए टोरंटो पुलिस यहां के रहने वाले 32 साल के अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है। टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी पुष्टि की और घटना पर हैरानी के साथ दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कहा, 'हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और सदमे में हैं। हम इस गहरे दुख की

घड़ी में उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं। ' भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने आगे कहा कि अधिकारी पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और कनाडाई अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों को सबसे पहले रात महिला के लापता होने की रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट किया गया था। पुलिस ने एक बयान में कहा, 'शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को रात करीब 10:41 बजे, पुलिस को स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक गुमशुदा शख्स को लेकर जानकारी दी गई। ' पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराधी की तलाश की जा रही है। मामले में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस ने एक तस्वीर भी साझा की और लोगों से मदद करने की अपील की है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'हमने आरोपी की तस्वीर सार्वजनिक की है। यदि किसी को उसके ठिकाने की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। फिलहाल आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पूरे कनाडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। '

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनात करने से रोका

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में भेजने से रोक दिया है, जिससे प्रशासन को झटका लगा है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, कोर्ट ने 6-3 वोटों से ट्रंप प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश एक ऑर्डर में कहा, 'इस शुरुआती स्टेज पर, सरकार ऐसा कोई अथॉरिटी सोर्स नहीं बता पाई है जो सेना को इलिनोइस में कानूनों को लागू करने की इजाजत दे। ' यह विवाद 4 अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को इलिनोइस में, खासकर शिकागो और उसके आसपास एक्टिव फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के अनुसार, अगले दिन टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरल सर्विस में शामिल किया गया और शिकागो भेजा गया।

9 अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अस्थाई रोक लगाने वाला ऑर्डर जारी किया, जिसमें इलिनोइस में नेशनल गार्ड को फेडरल

सर्विस में शामिल करने और उनकी तैनाती पर रोक लगा दी गई।

यह फैसला 16 अक्टूबर को सेवेंथ सर्किट के यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने बरकरार रखा, जिसने प्रशासन को नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने की इजाजत दी, लेकिन उनके सदस्यों को तैनात करने की नहीं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने 'फेडरल कानून लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को एक्टिव किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंगाई फेडरल इमारतों और प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं। ' इलिनोइस के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रिज्कर ने शिकागो के डेमोक्रेटिक मेयर के साथ मिलकर इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत' बताया।

जापान : क्योटो में फैला बर्ड फ्लू, सीजन में इस तरह का 9वां मामला

एजेंसी

टोक्यो। जापान के कृषि मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जेनेटिक टेस्टिंग में क्योटो प्रांत के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू (हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा) की पुष्टि हुई है। यह इस सीजन में देश में बर्ड फ्लू का नौवां मामला है। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार, यह मामला क्योटो प्रांत के कामेओका शहर में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में सामने आया है। इस फार्म में लगभग 2 लाख 80 हजार अंडे देने वाली मुर्गियां पाली जाती हैं। स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली। उसी दिन फार्म की मुर्गियों पर रैपिड एवियन इन्फ्लूएंजा टेस्ट किया गया, जिसके नतीजे पॉजिटिव आए। इसके बाद बुधवार को आनुवंशिक जांच से यह साफ हो गया कि यह गंभीर किस्म का एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस है। नियमों के अनुसार, फार्म की सभी मुर्गियों को मारकर नष्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें जलाकर जमीन में दफन

किया जाएगा। फार्म के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य फार्मों से मुर्गियों और अंडों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं, तीन से दस किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित फार्म बाहर के इलाकों में पोल्ट्री उत्पाद नहीं भेज सकेंगे। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वायरस के और फैलाव को रोकने के लिए फार्म के आसपास कीटाणुनाशक छिड़काव तेज कर दिया गया है। बीमारी की जांच के लिए एक विशेष टीम भी भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर मंत्रालय के विशेषज्ञ भी मौके पर जाएंगे। जापान में आमतौर पर बर्ड फ्लू का मौसम शरद ऋतु से लेकर अगले वसंत तक रहता है। इस मौसम में अब तक हुए आठ मामलों में करीब 24 लाख मुर्गियों को मारना पड़ा है।

देश में पहला मामला 22 अक्टूबर को सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो में सामने आया था। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लूएंजा भी कहा जाता है। यह एक बीमारी है जो जंगली पक्षियों और मुर्गियों में फैलती है। यह वायरस एच5एन1 और एच9एन2 जैसे सब-टाइप से होता है। कभी-कभी यह बीमारी इंसानों को भी हो सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलती। ज्यादातर मामलों में इंसान संक्रमित जीवित या मृत मुर्गियों के संपर्क में आने से बीमार हुए हैं।

संसद विघटन के खिलाफ दायर रिट में बहुमत सांसदों ने सर्वोच्च अदालत में आवेदन दिया

एजेंसी

काठमांडू। प्रतिनिधि सभा के विघटन के खिलाफ दायर रिट में अब 60 और सांसदों ने सर्वोच्च अदालत में आवेदन दिया है। नेपाली कांग्रेस के 57 तथा अन्य 3 सांसदों सहित कुल 60 सांसदों ने स्वयं को पहले से दायर रिट में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। इन सांसदों ने विघटित प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहित अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में शामिल कर मुकदमे का पक्ष बनाए रखने की मांग की है। घिमिरे समेत 8 सांसदों ने 9 दिसंबर को यह रिट दायर किया था। इस रिट पर 17 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक इजलास में प्रारंभिक सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने विपक्षी पक्षों को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। रिट विचाराधीन रहने के दौरान, उसके विषयवस्तु से अपने प्रत्यक्ष सरोकार, अधिकार और हित जुड़े होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त सांसदों ने मुकदमे में शामिल किए जाने की मांग की है। स्ताक्षर सौंपने वाले 60 सांसदों के आवेदन में कहा गया है, 'इस गैर-संवैधानिक कार्रवाई से हमारे संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ा है। इसलिए रिट याचिका में उल्लिखित तथ्यों के प्रति पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हम आवेदक भी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 के नियम 47(2) के अनुसार इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल होकर मुकदमे का पक्ष बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। '

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा अगले महीने कर सकते हैं भारत का दौराः सूत्र

एजेंसी

ब्रासीलिया। शीर्ष सूत्रों ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा जनवरी के अंत या फरवरी 2026 की शुरुआत में संभव हो सकता है। लूला का यह दौरा भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उम्मीद है कि प्रस्तावित दौरे के दौरान भारत और ब्राजील व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करेंगे। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। भारत और ब्राजील ब्रिक्स

और जी20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करीबी साझेदार हैं। इस दौरान वैश्विक आर्थिक मुद्दे, विकास संबंधी चिंताएं, और विकासशील देशों के बीच सहयोग भी चर्चा का विषय रहने की उम्मीद है। हालांकि, दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिससे भारत-ब्राजील संबंधों में निरंतर आ रही प्रगति पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए फेसबुक पर लिखा कि राष्ट्रपति लूला से मिलना हमेशा ही सुखद होता है। भारत और ब्राजील अपने लोगों के लाभ के लिए व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान प्राप्त हुई प्रगति की बार-बार पुष्टि की और भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रासीलिया में हुई थी।

पाकिस्तान की अदालत ने इमरान-बुशरा की कुछ मामलों में अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को आज एक अदालत से कुछ राहत मिल गई। संघीय राजधानी इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने इमरान और बुशरा बीबी की नौ मई के मामलों और पांच अन्य मामलों में अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ा दी। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को अगली सुनवाई में खुद या वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का निर्देश दिया। खान रावलपिंडी जेल (आदियाला जेल) में लंबे समय से बंद हैं। उन्हें कई मामलों में सजा हो चुकी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल माजोका ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। एडवोकेट शम्सा कयानी इमरान और बुशरा बीबी की ओर से पेश हुईं। हालांकि, इमरान की गैर मौजूदगी के कारण जमानत याचिकाओं पर बहस आगे नहीं बढ़ पाई। नतीजतन, अदालत ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी और सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। नौ मई के मामलों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या की कोशिश और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले भी दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना उपहारों से संबंधित कथित फर्जी रसीदें जमा करने का एक अलग मामला भी है। अदालत ने इस बीच बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका पर उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी और मामले को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया। इस बीच पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को तोशाखाना मामले में हालिया सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पर इमरान खान के हस्ताक्षर लेने के लिए उनसे मिलने की अनुमति एक बार फिर नहीं दी गई। पीटीआई ने तोशाखाना-2 मामले में पार्टी संस्थापक के अपील के अधिकार में जानबूझकर रुकावट डालने की निंदा की। पीटीआई ने कहा कि पंजाब जेल नियम, 1978 के नियम 178 और 179 के तहत हर कैदी को अपने वकील से मिलने, कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अपील दायर करने का कानूनी अधिकार है और जेल अधिकारियों को इस संबंध में बाधाएं पैदा करने का अधिकार नहीं है।

सुशीला कार्की सरकार के खिलाफ जेन जी समूह का दूसरे दिन भी प्रदर्शन

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सरकार के खिलाफ जेन-जी समूह का विरोध-प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है।आंदोलनकारी 8 और 9 सितंबर को हुए विद्रोह के बाद गठित पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाकर कल से ही आंदोलन कर रहे हैं। इस समय मैतीघर में प्रदर्शन जारी है, जहां मिराज ढुंगाना और निकोलस भुसाल सहित अन्य प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड के भीतर रहकर विरोध जता रहे हैं। आंदोलनकारी समूह ने अंतरिम प्रशासन के प्रति अपनी असंतुष्टि दोहराते हुए संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक दबावमूलक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मिराज ढुंगाना ने कहा कि जेनजी की भावना के विपरीत सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर जेनजी आंदोलनकारियों ने मंगलवार को भी काठमांडू के मैतीघर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने 'जेनजी की मांगें पूरी करो ', 'जेनजी की मांग चुनाव नहीं, सुशासन है' जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड प्रदर्शित किए।

बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव पर अमेरिकी सांसदों की चेतावनी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के कुछ प्रभावशाली सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इन सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए। यह पत्र अमेरिकी सांसद ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स, बिल हुइजेंगा और सिडनी कैमलैगर-डोव ने लिखा, जबकि जूली जॉनसन और थॉमस आर. सुओजी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। यूनुस को लिखे पत्र में सांसदों ने लिखा, 'हम बांग्लादेश में राष्ट्रीय संकट के समय अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आपके आगे आने की इच्छा का स्वागत करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए माहौल बनाए, जिससे लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के जरिए अपनी राय रख सकें। साथ ही ऐसे सुधार हों जो राज्य संस्थानों की निष्पक्षता और ईमानदारी में विश्वास बहाल करें। '

उन्होंने चिंता जताई कि अगर सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित करती है या फिर विवादित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दोबारा शुरू करती है, तो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और कमजोर हो सकता है।

अमेरिकी सांसदों ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिकी विदेश विभाग और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बांग्लादेश के 2018 और 2024 के आम चुनावों को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना था। उनका कहना है कि आने वाले चुनाव की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतरिम सरकार पहले की उन नीतियों से कितना अलग रास्ता अपनाती है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांसदों ने बताया कि 2024 में जुलाई और अगस्त के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि बदले की राजनीति का सिलसिला खत्म हो सके। सांसदों की सबसे बड़ी चिंता किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों को पूरी तरह निलंबित करने के फैसले को लेकर थी।

उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत बुनियादी मानवाधिकार हैं। किसी पूरे दल पर रोक उन सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने अंतरिम सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा और बताया कि सभी दलों की भागीदारी से ही जनता का भरोसा लौटाया जा सकता है। सांसदों ने कहा, 'आखिरकार, बांग्लादेश के लोगों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में चुनी हुई सरकार चुनने का अधिकार है, जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा ले सकें ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। '

पत्र में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिकी सांसद अंतरिम सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्तों और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर. सुओजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी।

page 1 and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 12/24/2025 11:42 PM Page 2

खेती करने का आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका

संरक्षित खेती का मतलब होता है खेती करने का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका जिसके अर्न्तगत पौधों को विपरीत प्रकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि से पौधों का बचाव किया जाता है पौधों को संरक्षण दिया जाता है और उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है जो कि उनकी बढ़वार में सहायक होती है और इस तरीके से उनसे अच्छी गुणवत्ता की और ज्यादा पैदावार प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं।

संरक्षित खेती के अंतर्गत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं जैसे पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस, ग्लास हाऊस, वाक-इन टनल, लो टनल इत्यादि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और सी.ओ.टू (कार्बन डाय आक्साईड) का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से जो खेती की जाती हैं उसे संरक्षित खेती कहते हैं। अगर हम ग्रीन हाऊस के बारे में बात करें तो ग्रीन हाऊस लोहे की पाईपों से बना एक ऐसा घर है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका रहता है। अगर ये पारदर्शी आवरण पॉलीथिन है तो इसे हम पॉली हाऊस कहते हैं पॉली हाऊस का इस्तेमाल आमतौर पर कट फ्लावर की खेती यानि डंडी वाले फूलों की खेती के लिए किया जाता है और डंडी वाले फूल जो लगाये जा सकते हैं वो हैं डच्च गुलाब, जरबेरा और कुछ जगहों पर हम कारनेशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेमौसमी सब्जियों की खेती भी पॉली हाऊस में की जा सकती है। शेडनेट के बारे में कहा जाता है शेडनेट लोहे की पाईपों से बना ऐसा ढांचा होता है जो कि हरे रंग की या सफेद रंग की जाली से या शेड नेट से ढ़का होता है। उसे हम शेडनेट करते हैं। शेडनेट हाऊस के अर्न्तगत हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं बेमौसमी सब्जियाँ लगा सकते हैं बेल वाले टमाटर, हरी, लाल, पीली, बैंगनी, नारंगी रंगों वाली शिमला मिर्च, धनियां, बीज रहित खीरा इत्यादि। सबसे अच्छा व्यवसाय तो नर्सरी का व्यवसाय है जिसको की आप शेडनेट हाऊस के अन्दर कर सकते हैं। इसके अन्दर आप सब्जियों की पौध भी तैयार कर सकते हैं उसके लिए आप को चाहिए प्लास्टिक की प्रो ट्रे या नर्सरी ट्रे जिसमें की लगभग अठयानवें छेंद होते हैं उन छेदों के अन्दर कोको पिट एवं वर्मीकम्पोस्ट भरा जाता है और कोको पिट भरने के पश्चात उनमें एक-एक बीज लगा दिया जाता है इस तरीके से पौध तैयार की जाती है टमाटर की पौध तैयार होने में लगभग 25 से 28 दिन लगते हैं। शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च की पौध तैयार करने में 35 से 40 दिन लगते हैं और वैसे ही अगर आप खीरे की पौध तैयार करना चाह रहे हैं सर्दियों के अन्दर, तो सर्दियों में लगभग आप को 20 से 21 दिन लगते हैं और गर्मियों में यह 15 से 18 दिन में तैयार हो जाती है।

'लो टनल' लो टनल का मतलब होता है छोटी सुरंगनुमा संरचना या एक ढ़ाचा जो कि छोटा सुरंगनुमा आकार का होता है खासतौर से इसको बनाया जाता है लगभग जब तेज सर्दियां पड़ती हैं दिसम्बर, जनवरी माह में (15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक) इसको बनाया जाता है और पहले एक मीटर की बेड बनाई जाती है जो की ऊपर से 90 से.मी. होती है और उसके ऊपर यू शेप या अर्द्धचन्द्राकार में पाईप या लोहे का तार लगा दिया जाता है प्लास्टिक की पाईप या मोटा तार बेन्ड करके लगा दिया जाता है और उसको हर ढाई से तीन मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसे हुप्स कहा जाता है और इन हुप्स को ऊपर से पॉलीथिन से ढ़क दिया जाता है और उसके अन्दर खेती की जाती है। पॉलिथिन के स्थान पर नोन वोवन प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसमे छेद करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की खेती जो कि लो टनल के अन्दर की जाती है ये आमतौर पर सर्दियों में की जाती है। कुछ सब्जियां या फसलें होती हैं जो उग नहीं पाती सर्दियों की वजह से परन्तु इस तरीके की सुरंगनुमा लो टनल बनाकर उसके अन्दर अच्छी तरह से ना केवल उगाई जा सकती है बल्कि अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद एवं ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है

मिट्टी में सुधार कैसे करें

सभी माली को कभी-कभी जमीन के एक टुकड़े की मिट्टी में सुधार की चुनौती का सामना करना पड़ता है। खेती के लिए सभी मिट्टी में अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि, मिट्टी में सुधार कृषि श्रमिकों के लिए एक आम काम है (चाहे एक छोटी परियोजना में लगे हों या बड़े हिस्से में)। मिट्टी को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए विशिष्ट कौशल और रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। मिट्टी में सुधार करने और भूमि के एक टुकड़े के प्रभावी उपज को बढ़ाने के लिए यहां कुछ सबसे अधिक अनुशंसित विधियां दी गई हैं।

मिट्टी पोषक तत्वों में सुधार करें

1 जांच लें कि आपके पौधों की ज़रूरत क्या है बागवानी के लिए तीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं- पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन (एन) और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जड़ों, फलों और बीज और पोटेशियम (के) के लिए फास्फोरस (पी), पौधों की सामान्य स्वास्थ्य पत्तियों के विकास पर ध्यान देने के लिए रोपाई को अधिक फॉस्फोरस की आवश्यकता हो सकती है और पौधों को आमतौर पर इन पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है जब यह मौसम नहीं बढ़ रहा है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, विशिष्ट पौधों की जांच करें ताकि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। इन्हें आम तौर पर तीन मानों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है एनपीके, जो उस क्रम में इन पोषक तत्वों के अनुपात या कुल मात्रा को दर्शाते हैं।

2 कार्बनिक स्रोतों से उर्वरक चुनें पौधे के मामले और पशु पदार्थ (जैसे मछली का पायस या मछली हाइड्रोलाइजेट) लंबी अवधि के माइक्रोबियल विकास के लिए सर्वोत्तम प्रकार के उर्वरक प्रदान करते हैं, जो मिट्टी को पोषक तत्वों और छिद्रपूर्ण समृद्ध रखती हैं। प्रयोगशालाओं में संश्लेषित उर्वरक आम तौर पर मिट्टी में सुधार किए बिना पौधे को भोजन करते हैं और कुछ मामलों में, वे नकारात्मक प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं।

मिट्टी के additives के साथ काम करते समय हमेशा अपने हाथों और चेहरे की रक्षा करें, क्योंकि ये कुछ बैक्टीरिया और अन्य स्वास्थ्य खतरों के होते हैं।

3 खाद या अन्य कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने पर विचार करें विनिर्मित उर्वरकों के बजाय, आप एक बगीचे की आपूर्ति की दुकान या खेत पर सस्ता, अप्रसारित उर्वरक पा सकते हैं। ये कुछ सामान्य विकल्प हैं पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए आपको खाद को कम से कम एक महीने का उपयोग करने से पहले सिकोड़ना चाहिए। चिकन या टर्की खाद किफायती है, लेकिन बड़े क्षेत्रों में अपवाह समस्याओं का कारण हो सकता है। गाय, भेड़, बकरी और खरगोश की खाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं और कम सख्त गंध है। फास्फोरस या नाइट्रोजन के लिए खून के भोजन के लिए हड्डी का भोजन जोड़ें।

4 अपना खुद का खाद बनाएं, नए खाद को आमतौर पर परिपक्व होने में चार से आठ महीने लगते हैं, जब तक कि आप विशेष जीवाणुओं को जोड़कर इस प्रक्रिया को गति नहीं देते। यदि आप इस प्रक्रिया के साथ जारी रखने के लिए तैयार हैं तो यह दीर्घकालिक परियोजना, मिट्टी और पोषक तत्वों की बनावट दोनों को बहुत फायदा पहुंचेगी। एक बड़े बाहरी कंटेनर को अलग रखें जो कि इसे जानवरों से बचाने के लिए हीमेटिक रूप से सील किया गया है, लेकिन छिद्रों के साथ हवा को प्रसारित करने के लिए तकनीकों के साथ इसकी देखभाल करें

काबुली चने की खेती कैसे करें

काबुली चना की खेती देशी चने की तरह ही की जाती है. काबुली चने को डॉलर और छोला चना भी कहा जाता है. काबुली चने का पौधा सामान्य (देशी) चने से बड़ा होता है. इसके पौधे पर फलियों (टाट) देरी से बनती है. इसके पौधे देशी चने से ज्यादा वक्त बाद पकते हैं. काबुली चनो का रंग हल्का सफ़ेद या हल्का गुलाबी पाया जाता है. जिनका आकार सामान्य चने से काफी बड़ा पाया जाता हैं. काबुली चने का इस्तेमाल सब्जी के साथ साथ छोले और भूनकर खाने में ज्यादा किया जाता है. इसको खाने से कई तरह के रोगों में फायदा मिलता है. जिनमें पथरी, मोटापा और पेट संबंधित बिमारियों में यह लाभदायक होता है।

काबुली चने की खेती के लिए शरद जलवायु की जरूरत होती है. इसके पौधे अधिक तेज़ गर्मी के मौसम में अच्छे से विकास नही कर पाते. इसके पौधों को बारिश की सामान्य जरूरत होती है. काबुली चने की खेती के लिए सिंचाई की जरूरत होती है. इसकी खेती के लिए भूमि का पी. एच. मान सामान्य 7 के आसपास होना चाहिए. काबुली चने का वर्तमान में उपयोग काफी बढ़ चुका है. काबुली चना किसानों के लिए काफी लाभ देने वाली खेती है. जिसको देखते हुए अब इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है।

अगर आप भी काबुली चने के माध्यम से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसकी खेती के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

उन्नत किस्में

काबुली चने की काफी उन्नत किस्में बाजार में उपलब्ध हैं. जिन्हें अलग अलग जगहों पर अधिक पैदावार लेने के लिए तैयार किया गया है।

श्वेता

काबुली चने की इस किस्म को जल्द पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है. जिसे आई सी सी व्ही 2 के नाम से भी जानते हैं. इसके दाने मध्य मोटाई वाले आकर्षक दिखाई देते हैं. जो बीज रोपाई के लगभग 85 से 90 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं. इस किस्म के पौधों का प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 15 से 20 क्विंटल के बीच पाया जाता है. काबुली चने की इस किस्म को सिंचित और असिंचित दोनों जगहों पर आसानी से उगाया जा सकता है. इसके दाने छोले के रूप में अधिक स्वादिष्ट होते हैं.

मेक्सीकन बोल्ड

चने की ये एक विदेशी किस्म है, जिसके पौधे सामान्य ऊंचाई के पाए जाते हैं. इस किस्म के पौधों को असिंचित भूमि में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है. इसके पौधे रोपाई के लगभग 90 से 100 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं. इसके दाने आकार में मोटे दिखाई देते हैं. जिनका रंग बोल्ड सफेद और चमकदार पाया जाता है. जो काफी आकर्षक दिखाई देते हैं. इसके दानो का बाजार भाव काफी अच्छा मिलता है. इसके पौधों का प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 25 से 35 क्विंटल के बीच पाया जाता है. लेकिन फसल की देखभाल अच्छे से की जाए तो पौधों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. इसके पौधों पर कीट रोग का प्रभाव काफी कम देखने को मिलता है.

हरियाणा काबुली न. 1

चने की इस किस्म को मध्यम समय में अधिक पैदावार देने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा तैयार किया गया है. इस किस्म के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 130 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 25 से 30 क्विंटल के बीच पाया जाता है. काबुली चने की इस किस्म को बारानी भूमि को छोड़कर लगभग सभी तरह की भूमि में उगा सकते हैं. इसके पौधे अधिक शखाओं युक्त फैले हुए होते हैं. इसके दानो का आकार सामान्य और रंग गुलाबी सफ़ेद होता है. इसके पौधों में उकठा रोग काफी कम देखने को मिलता है.

चमत्कार

काबुली चने की इस किस्म के पौधे सामान्य ऊंचाई और कम फैलने वाले होते हैं. इसके पौधों पर पत्तियां बड़े आकार वाली पाई जाती हैं. इसके पौधे रोपाई के लगभग 130 से 140 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं. इसके पौधों का प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 15 से 18 क्विंटल के बीच पाया जाता है. जिसके दानो का आकार बड़ा दिखाई देता है. इसके पौधों पर उकठा रोग देखने को नही मिलता.

काक 2

चना की ये एक मध्यम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म हैं. इसके पौधे सामान्य ऊंचाई के पाए जाते हैं. जिन पर उकठा रोग देखने को नही मिलता. इसके पौधे रोपाई के लगभग 110 से 120 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 15 से 20 क्विंटल के बीच पाया जाता है. इसके दाने सामान्य मोटाई और हल्के गुलाबी रंग के पाए जाते हैं.

एच. के. न. 2

काबुली चने की इस किस्म को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा तैयार किया गया है. इस किस्म के पौधे रोपाई के लगभग 120 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 से 25 क्विंटल के बीच पाया जाता है. जिसे हरियाणा के आसपास के राज्यों में उगाया जाता है. इस किस्म के पौधे कम ऊंचाई और सीधे बढ़ने वाले होते हैं. जिसकी पत्तियों का रंग हल्का हरा दिखाई देता है.

जे.जी.के 1

काबुली चने की की इस किस्म को मध्य प्रदेश में अधिक उगाया जाता है. इस किस्म के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 120 दिन के बीच पककर तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 15 से 18 क्विंटल के बीच पाया जाता है. इसके दानो का रंग हल्का सफ़ेद या क्रमी सफेद पाया जाता है. इस किस्म के पौधे सामान्य लम्बाई के और कम फैलने वाले होते हैं. इसके पौधों पर पत्तियां बड़े आकार वाली और फूल सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं.

जे.जी.के 2

काबुली चने की इस किस्म के पौधे कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए जाने जाते हैं. इस किस्म के पौधे रोपाई के लगभग 100 से 110 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं. इसका इस्तेमाल छोले के रूप में भी किया जाता है. इस किस्म के पौधे कम फैलाव वाले पाए जाते हैं. जिसकी पतियों का आकार बड़ा और फूलों का रंग सफेद होता है. इसके दाने सामान्य आकार और हल्के सफेद रंग के पाए जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 क्विंटल तक पाया जाता है.

एस आर 10

चने की इस किस्म को राजस्थान में अधिक उगाया जाता है. इस किस्म के पौधे सिंचित और असिंचित दोनों तरह की भूमि में उगाये जा सकते हैं. इस किस्म के पौधे असिंचित जगहों पर रोपाई के के दौरान लगभग 140 दिन के आसपास पककर तैयार होते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 से 25 क्विंटल के बीच पाया जाता है. इस किस्म के पौधों पर कई तरह के रोग देखने को नही मिलते.

पूसा 1003

डॉलर चने की इस किस्म को उत्तर प्रदेश में अधिक उगाया जाता है. जिसके पौधे रोपाई के लगभग 130 से 140 दिन बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 से 22 क्विंटल तक पाया जाता है. इसके दाने मध्यम बड़े आकार के पाए जाते है. इसके पौधे उकठा रोग के प्रति सहिष्णु होते हैं.

शुभ्रा

चने की इस किस्म के पौधे सामान्य ऊंचाई के पाए जाते हैं. जिनको सिंचित और असिंचित दोनों तरह की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है. इस किस्म के पौधे सूखे के प्रति सहनशील पाए जाते हैं. इसके पौधे रोपाई के लगभग 120 से 125 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं. जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 क्विंटल के आसपास पाया जाता है. इस किस्म के पौधों पर उकठा रोग का प्रभाव देखने को नही मिलता.

इनके अलावा और भी काफी किस्में हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर वातावरण के हिसाब से अधिक उत्पादन लेने के लिए उगाया जाता है. जिनमें एच.के. 94-134, सी एस जे के 54, उज्जवल,अंजलि, गौरी, पंत काबुली 1, आसार, राज विजय काबुली 101, आनंद और जे.जी.के 3 जैसी बहुत साड़ी किस्में मौजूद हैं.

पौधों की सिंचाई

डॉलर चने के पौधों को देशी चने से ज्यादा पानी की जरूरत होती है. इसलिए इसके पौधों की रोपाई के लगभग 50 दिन के आसपास पौधों की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए. उसके बाद इसके पौधों की दूसरी सिंचाई फलियों में दाने बनने के दौरान करनी चाहिए. और इस दौरान अगर बारिश हो जाए तो पौधों की दूसरी सिंचाई नही करनी चाहिए. चने के पौधों में फूल बनने के दौरान कभी भी सिंचाई नही करनी चाहिए. इससे फसल खराब हो जाती है. इसके पौधों की दो सिंचाई काफी होती है. लेकिन पानी की उचित व्यवस्था हो तो दानो के पकने के दौरान एक हल्की सिंचाई करने से दाने अच्छे से पकते हैं. और पैदावार भी अधिक प्राप्त होती हैं.

उर्वरक की मात्रा

चने के पौधों को उर्वरक की ज्यादा जरूरत नही होती. इसके पौधे खुद भूमि में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं. जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढती है. इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की जुताई के वक्त दी जाने वाली 10 से 12 गाडी गोबर की खाद काफी होती हैं. और जो किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहता है वो इसकी इसके बीजों की रोपाई से पहले 50 किलो डी.ए.पी. की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिडक दें.

उपयुक्त मिट्टी

काबुली चने की खेती सभी तरह की भूमि में की जा सकती है. लेकिन उन्नत पैदावार लेने के लिए इसे हल्की दोमट मिट्टी में उगाना चाहिए. इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नही होना चाहिए. जलभराव होने से इसकी खेती में कई तरह के रोग लग जाते हैं. इसकी खेती के लिए भूमि का पी. एच. मान 7 के आसपास होना चाहिए.

जलवायु और तापमान

काबुली चने की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है. इसके पौधे को विकास करने के लिए सर्दी के मौसम की जरूरत होती है. लेकिन सर्दियों में अधिक समय तक पड़ने वाला पाला इसकी फसल के लिए नुकसानदायक होता है. गर्मी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त नही होता. गर्मी के मौसम में इसके पौधे विकास नही कर पाते हैं. और उन पर कई तरह के रोग लग जाते हैं. जिसका असर इसकी पैदावार पर देखने को मिलता है. इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है. चने की खेती के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है. शुरुआत में इसके पौधों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री के आसपास तापमान की आवश्यकता होती है. उसके बाद इसके पौधे सर्दियों के मौसम में 10 डिग्री के आसपास तापमान पर भी आसानी से विकास कर लेते हैं. जबकि दानो के पकने के दौरान इसके पौधे को 25 से 30 डिग्री के बीच तापमान की जरूरत होती है.

खरपतवार नियंत्रण

चने की खेती में कई तरह की खरपतवार जन्म लेती हैं. जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण कर पौधों के विकास को रोक देती हैं. जिसका असर पैदावार पर देखने को मिलता है. जिनका समय रहते इनका नियंत्रण करना जरूरी होता है. काबुली चने की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है. रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बीज रोपाई के तुरंत बाद खेत में पेन्डीमेथालीन की उचित मात्रा का छिडकाव कर देना चाहिए. इसके अलावा प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पौधों की नीलाई गुड़ाई कर उनमें खरपतवार नियंत्रण किया जाता है. इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज अंकुरित होने के लगभग 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए. उसके बाद दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के लगभग 20 दिन बाद करनी चाहिए. इसके पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए दो गुड़ाई काफी होती है.

काबुली चने के पौधों में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं. जिनकी रोकथाम समय रहते ना की जाये तो पौधों की पैदावार और उनके विकास पर प्रभाव देखने को मिलता हैं.

उकठा रोग

इसके पौधों में उकठा रोग फफूंद की वजह से फैलता है. पौधों पर इस रोग का प्रभाव बीज रोपाई के लगभग तीन से चार सप्ताह बाद ही दिखाई देने लगता है. इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों का रंग हल्का पीला दिखाई देने लगता है. रोग बढ़ने पर पत्तियां सुखकर गीरने लगती है. जिस कारण पौधे का विकास रुक जाता है. जिसके कुछ दिन बाद सम्पूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है. इस रोग की रोकथाम के लिए शुरुआत में बीजों को कार्बेन्डाजिम या बाविस्टीन की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए. इसके अलावा खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर पौधों पर कार्बेन्डाजिम की उचित मात्रा का छिडकाव करना चाहिए.

हरदा रोग

चने के पौधों में यह रोग यूरोमाईसीज साइसरीज नामक फफूंद की वजह से फैलता है. पौधों पर इस रोग का प्रभाव मौसम में अधिक नमी के बने रहने और पाला के पड़ने के दौरान दिखाई देता है. इस रोग के लगने से पौधे के तने और शाखाओं पर सफेद रंग के फफोले बन जाते हैं. रोग बढ़ने पर इन फफोलों का रंग काला दिखाई देने लगता है. और कुछ दिन बाद पौधे पूरी तरह सूखकर नष्ट हो जाते हैं. इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर रोग दिखाई देने के तुरंत बाद मैंकोजेब की उचित मात्रा को पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल में दो बार छिडक दें.

चने के पौधों में इस रोग का प्रभाव फसल के पकने के दौरान दिखाई देता है. जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण फैलता हैं. इस रोग के लगने पर शुरुआत में पौधे की पत्तियों और शाखाओं पर भूरे काले रंग के चित्ते दिखाई देने लगते हैं. रोग के बढ़ने से इन धब्बों का आकार बढ़ जाता है. जिससे पौधों की पैदावार प्रभावित होती है. इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर मैंकोजेब, गंधक या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उचित मात्रा का छिडकाव 10 दिन के अंतराल में 2 से तीन बार करना चाहिए.

कटुआ कीट

चने के पौधों में कटुआ कीट रोग का प्रभाव पौधों के विकास के दौरान देखने को मिलता है. इस रोग की सुंडी पौधे की जड़ के पास से काटकर पौधों को नष्ट कर देती हैं. जिससे पौधा तुरंत खराब हो जाता है. इसकी सुंडी पौधों को रात के मौसम में काटती है. और दिन के मौसम में मिट्टी में छुप जाती है. रोग के बढ़ने पर सम्पूर्ण फसल खराब हो जाती है. इस रोग की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास की ढाई लीटर मात्रा को पानी में मिलाकर खेत की जुताई के वक्त खेत में छिडक देना चाहिए. इसके अलावा फोरेट का इस्तेमाल भी करना अच्छा होता है.

फली छेदक

डॉलर चने के पौधों मे फली छेदक रोग कीट वजह से फैलता है. इस रोग के कीट की सुंडी का रंग हल्का हरा दिखाई देता है. जो पौधों पर फली बनने के दौरान दिखाई देती है. इसकी सुंडी पौधे की फलियों में छेद कर अंदर चली जाती हैं. और फलियों में पाए जाने वाले दानो को खाकर उन्हें खराब कर देती है. रोग बढ़ने से इसका असर ज्यादातर पौधों पर देखने को मिलता हैं. जिससे पौधों से प्राप्त होने वाली पैदावार को सबसे ज्यादा नुक्सान पहुँचाता है. इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर स्पाइनोसेड या इन्डोक्साकार्ब की उचित मात्रा का 2 बार छिडकाव करना चाहिए. इसके अलावा रोग दिखाई देने पर नीम के तेल का छिडकाव पौधों पर दस दिन के अंतराल में दो बार करना चाहिए.

पैदावार और लाभ

काबुली चने के दाने सामान्य चने से मोटे पाए जाते हैं. जिसकी विभिन्न किस्मों का प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 20 क्विंटल से ज्यादा पाया जाता है. और इसका बाजार भाव 6 हजार प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है. इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर से सालाना सवा लाख के आसपास कमाई कर सकता है।

बीज रोपाई का तरीका

काबुली चने के बीजों की रोपाई मशीनों के माध्यम से की जाती है. मशीन के माध्यम से रोपाई के दौरान इसके बीजों को पंक्तियों में उगाया जाता है. पंक्तियों में बीजो की रोपाई के दौरान प्रत्येक पंक्तियों के बीच एक फिट की दूरी होनी चाहिए. और पंक्तियों में उगाये गए बीजों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए. काबुली चने के बीजों की रोपाई के दौरान उन्हें 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में उगाना चाहिए. ताकि बीजों का अंकुरण अच्छे से हो पाए.

काबुली चने की खेती रबी की फसलों के साथ की जाती है. लेकिन सिंचित और असिंचित जगहों के आधार पर इनकी रोपाई अलग अलग समय पर की जाती हैं. सिंचित जगहों पर रोपाई के दौरान इसके बीजों की रोपाई अक्टूबर माह के आखिर तक कर देनी चाहिए. और असिंचित जगहों पर इसकी रोपाई बारिश के आधार पर की जाती है.

खेत की तैयारी

काबुली चने की खेती के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी होता है. इसके लिए शुरुआत के खेत की गहरी जुताई कर उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें. जिससे मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं. खेत को खाली छोड़ने के बाद उसमें लगभग 10 से 12 गाडी पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला दें. खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से दो तिरछी जुताई कर दें.

खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मौजूद ढेलों को नष्ट कर खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल बना दे. उसके बाद बारिश होने के तुरंत बाद इसके दानों की रोपाई कर दें. लेकिन जिन किसान भाई के पास सिंचाई उचित व्यवस्था हो वो खेत का पलेव कर और फिर से खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर बीज की रोपाई टाइम से कर सकता है.

बीज की मात्रा और उपचार

डॉलर चने की प्रति एकड़ रोपाई के लिए लगभग 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होती हैं. इसके बीजों की खेत में रोपाई से पहले उन्हें कार्बेन्डाजिम, मैंकोजेब या राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए. इससे दानो के अंकुरण के वक्त लगने वाले रोगों का प्रभाव काफी कम देखने को मिलता है.